राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 27 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-236 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

फॉर्म-6 में किया बदलाव पूरी तरह अवैध चुनाव आयोग के पास संशोधन का अधिकार नहीं

रमेश बोले- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह ठहराना चाहिए

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े विवाद के बीच शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को युवा मतदाताओं के लिए विशेष नामांकन शिविर आयोजित करने और सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया।

रमेश ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में किया गया बदलाव ÷पूरी तरह अवैध÷ है और निर्वाचन आयोग के पास इसमें एकतरफा संशोधन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जुलाई, 2026 की शुरुआत में ऑनलाइन फॉर्म में बिना किसी आधिकारिक अधिसूचना के बदलाव किया गया और उसमें एक नया अनिवार्य खंड जोड़ा गया, जिसमें आवेदकों से यह जानकारी मांगी कि उनके माता-पिता या दादा-दादी पिछले एसआईआर में शामिल थे या नहीं। रमेश ने कहा कि यह प्रावधान खासकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए बाधा पैदा करता है। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म-6 में संशोधन करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के बजाय केंद्र सरकार के पास है और ऐसा बदलाव संबंधित नियमों में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमेश ने 'पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960' का हवाला देते हुए दावा किया कि फॉर्म में बदलाव के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन और संसद को इसकी सूचना दिया जाना जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव को ÷अवैध और अनधिकृत÷ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी ताकि युवा और पहली बार मतदाता बनने

वाले लोग बिना परेशानी के अपना पंजीकरण करा सकें। रमेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में संवैधानिक परंपराओं और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन हुआ।

जयशंकर की लावरोव और अराघची से हुई मुलाकात

द्विपक्षीय संबंधों और खाड़ी संघर्ष पर चर्चा

न्यूयॉर्क ।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सत्र से इतर रूस और ईरान के अपने समकक्षों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और ब्रिक्स में सहयोग समेत विभिन्न मौजूदा मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और द्विपक्षीय संबंधों तथा ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। भारत ने इसी महीने ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल हुए थे। जयशंकर की लावरोव से मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब भारत और रूस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग जारी है। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष और उससे जुड़े ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। जयशंकर ने बैठक को उपयोगी बताया।इस बीच संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक कार्यक्रम के बाद पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर और पत्रकार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यंती समुद्री परिवहन और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा से जुड़े 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स'पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।इसी दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया। जयशंकर ने जवाब में पाकिस्तान को आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि जिस देश से यह सवाल पूछा जा रहा है, उसे पहले अपने रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने भी पत्रकार से कहा कि उन्हें अपना जवाब मिल चुका है। इससे एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र परिसर में प्रवेश करते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी आतंकवाद को लेकर सवाल पूछा गया था।

सीएम मान ने बेअदबी कानून पर बुलाई मीटिंग

आज चंडीगढ़ आवास पर जुटेगी 7 सदस्यीय समिति; कानून के अमल-रणनीति पर होगा मंथन

अमृतसर।

पंजाब सरकार ने जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में बनी 7 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक 27 सितंबर, रविवार को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगी। बैठक में संशोधित अधिनियम के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून को जमीन पर लागू करने के प्रस्तावों, प्रक्रिया और संबंधित पक्षों के बीच तालमेल पर भी बात की जाएगी।सरकार की 7 सदस्यीय समिति का काम संशोधित कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति बनाना और हितधारकों के बीच तालमेल बिठाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक कानून के अमल की दिशा तय करेगी। जत्थेदार गडग़ज़ ने 30 सितंबर तक दिया था अल्टीमेटम बेअदबी कानून पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गडग़ज़ ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया था। जत्थेदार ने सरकार को कहा था कि तय समयसीमा यानी 30 सितंबर तक कानून की धाराओं में बदलाव नहीं करने पर अकाल तख्त इस मामले में सख्त फैसला लेगा। जत्थेदार ने उम्मीद जताई थी कि सरकार तय समय पर बदलाव कर देगी। बेअदबी के मामलों की जांच को कड़े निर्देश हो चुके जारीपंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों की बेअदबी के मामलों की जांच को लेकर पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कड़े और नए दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है।

गुरुग्राम में पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी की पत्नी की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत

घरेलू कलह और प्रताड़ना का आरोप

गुरुग्राम ।

गुरुग्राम के सोहना-दोहला रोड पर स्थित एमवीएन सोसाइटी के टावर-8 में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां तीसरी मंजिल से नीचे गिरने के कारण दीपा नामक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका दीपा सोसाइटी के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी जतिन की पत्नी थीं। इस घटना के बाद से लोकल निवासियों में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोहना सिविल अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। दीपा के मायके पक्ष और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर कहा है कि वह अपने पति की रोज-रोज की प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न से भारी तनाव में थीं। परिजनों का दावा है कि जतिन अक्सर शराब के नशे में घर आकर उनके साथ मारपीट करते थे। पारिवारिक कलह और घरेलू हिंसा के इस निरंतर दौर से तंग आकर ही दीपा ने यह खौफनाक कदम उठाया।

नागालैंड में जहरीली शराब का तांडव 19 लोगों की मौत,जाँच जारी

नागालैंड ।

नागालैंड में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया है, इससे राज्य के मोकोकचुंग और तुएनसांग जिलों में करीब 19 लोगों की कथित तौर पर मौत हुई है। बीते दो दिनों में सामने आईं इन दुखद घटनाओं ने प्रशासन को हिला दिया है। मोकोकचुंग में आठ और तुएनसांग में ग्यारह लोगों ने संदिग्ध अवैध शराब पीने के बाद मौत हो गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागालैंड में 1990 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है, जो इस त्रासदी को गंभीर बनाती है।

इन मौतों के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखकर संदिग्ध मिलावटी शराब के स्रोत और उसकी पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आई बुंगलांग चांग कर रहे हैं, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेसुप्रा केजो की देखरेख में काम कर रही है। मौत की असली वजह और शराब की प्रकृति जानने के लिए, संदिग्ध शराब के सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेज दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन

विस्तृत जानकारी का खुलासा करना अभी जल्दबाजी होगी।

पुलिस ने प्रभावित इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाए। इस कार्रवाई के तहत, अब तक 19 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और बाजार से करीब 3,000 बोतलें संदिग्ध शराब जब्त की हैं।

जिला अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे बिना पहचान, बिना लेबल या संदिग्ध अवैध शराब का सेवन बिल्कुल न करें।

अगर गठबंधन नहीं करना है तो न करें, हम क्या किसी से भीख मांग रहे हैं ?

इकरा हसन के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया पलटवार

नई दिल्ली।

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान शुरु हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं करना है तो न करें। हम अपने काम पर लगे हैं। सांसद मसूद ने कहा कि न करें गठबंधन, कौन कह रहा है? हम क्या किसी से भीख मांग रहे हैं? जिसको जो करना है, वह करे। जब बारात चढ़ती है, तो बहुत सारे ढोल बजाने वाले भी होते हैं, नाचने-गाने वाले भी होते हैं। इन नाचने-गाने वालों को नाचने-गाने दीजिए। हम अपने काम पर लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सपा विधायक शिवपाल यादव के बयान पर मसूद ने कहा कि यह उनकी सोच हो सकती है, कांग्रेस अपने काम पर लगी है। शिवपाल जो बात कह रहे हैं, वह पार्टी के अंदर ही अप्रासंगिक हो गए हैं। वह अपने नेता से यह बात अगर वह कहेंगे, तब तो उसके ऊपर कोई मायने होंगे, इसके अलावा कोई मायने नहीं हैं। मसूद ने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बता दें इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलना है। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों से इंडिया गठबंधन आहत होता है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी को लाभ देने वाले बयान कांग्रेस की ओर से आते रहे हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव तय करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए हैं। कांग्रेस यूपी-बिहार में कितना पानी में है, यह जगजाहिर है।

बेल्जियम से आया 308 पहियों वाला ट्रक 4 राज्यों से गुजरेगा

नई दिल्ली ।

इन दिनों 308 पहियों वाला एक विशालकाय ट्रक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बेल्जियम से समुद्री रास्ते से लाई गई करीब 200 टन वजनी एक औद्योगिक मशीन को यह विशेष ट्रेलर उत्तर प्रदेश ले जा रहा है। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर उतारी गई इस मशीन को 308 पहियों वाले हाइड्रोलिक मॉड्यूलर ट्रेलर पर लोड किया गया, जिसका अंतिम गंतव्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल की इकाई है। यह ट्रक ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा।

इतने बड़े आकार और अत्यधिक वजन के कारण इस ट्रक का सफर सामान्य वाहनों जैसा नहीं है। इसकी औसत रफ्तार महज 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और यह 24 घंटे में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाता है। अत्यधिक भार और सुरक्षा कारणों से इसे तेज गति से चलाना जोखिम भरा होता है। सड़क की भार क्षमता, तीव्र मोड़ लेने की क्षमता, वाहन की विशाल लंबाई-चौड़ाई और ऊपर से गुजरने वाले तारों की ऊंचाई जैसे कई तकनीकी पहलू इसकी धीमी गति के लिए जिम्मेदार हैं। रास्ते में आने वाली भौतिक और तकनीकी बाधाओं को हटाना पड़ रहा है। वाराणसी के मोहनसराय के पास कम ऊंचाई वाले फुट ओवरब्रिज के कारण ट्रक को कई दिनों तक रोका गया। वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से निकालने के लिए बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी और कुछ समय के लिए रेल यातायात भी रोकना पड़ा। जहां भी कम ऊंचाई वाले पुल या हाईटेंशन तार सामने आते हैं, वहां प्रशासन और तकनीकी टीम रास्ता सुरक्षित बनाती है, जिसमें कई बार पुलों को हटाने या दोबारा बनाने और तारों को स्थानांतरित करने का भुगतान भी शामिल है। यह बाहुबली ट्रक ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इसके मार्ग में ओडिशा के पारादीप, दुबुरी, पितरी, पल्लाहारा और राउरकेला के बाद झारखंड के गुमला, रांची और बरही शामिल हैं। इसके बाद बिहार में औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर से गुजरते हुए यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और लखीमपुर तक पहुंचेगा। इस पूरे परिवहन अभियान पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें रूट मैपिंग, सर्वे, विभिन्न विभागों की अनुमतियां, 40-50 सदस्यों वाली क्रू और इंजीनियरिंग टीम का खर्च, तथा रास्ते की बाधाओं (पुल, तार) को हटाने या पुनर्निर्मित करने की लागत शामिल है। यह खर्च संबंधित कंपनी द्वारा वहन किया जा रहा है।

ट्रक पर लदा औद्योगिक वैक्यूम पैन वेसल, जिसे सरकारी दस्तावेजों में 'साइक्लाइजेशन रिएक्टर' बताया गया है, लोहे और विशेष मिश्रधातु से बना करीब 200 मीट्रिक टन वजनी बेलनाकार ढांचा है।

केदारनाथ यात्रा दो दिन के लिए रोकी गई

रुद्रप्रयाग।

मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने केदारनाथ धाम यात्रा को शनिवार दोपहर से 27 सितंबर तक स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। खराब मौसम के चलते शनिवार को केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी संचालित नहीं हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

इसके चलते देश-विदेश से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा स्थगित की गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग के सभी सेक्टर अधिकारी, चेकपोस्ट और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मौसम सामान्य होने के बाद केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सैटेलाइट तस्वीर में भारत में मौसम दो हिस्सों में बंटा दिखा, आधे में घने बादल तो आधा साफ

इसरो के अत्याधुनिक इनसेट-3डीएस ने भारत के आसमान से अद्भुत दृश्य किया कैद

नई दिल्ली।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अत्याधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसेट-3डीएस ने भारत के आसमान से एक अद्भुत दृश्य कैद किया है। शुक्रवार को ली गई इस सैटेलाइट तस्वीर में भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटा नजर आया। देश का पूर्वी और दक्षिणी भाग जहां घने बादलों के आगोश में है, वहीं पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हिस्से में आसमान पूरी तरह साफ दिख रहा है। तस्वीर में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर वायुमंडलीय स्थितियों में एक अनोखा बंटवारा दिख रहा है। इसमें पूर्वी भारत, बंगाल की खाड़ी और आस-पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बादल बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10.83 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ वाले थर्मल इन्फ्रारेड चैनल का इस्तेमाल करके ली गई यह सैटेलाइट तस्वीर भारत और पड़ोसी देशों में बादलों के फैलाव को दिखाती है।

इसकी सबसे खास बात बादलों का एक बड़ा और चमकदार समूह है जो बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत तक फैला है। इसके अलावा, दक्षिणी प्रायद्वीप और आस-पास के समुद्री इलाकों में भी बादलों की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। इसके उलट, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत का ज्यादातर हिस्सा बादलों से मुक्त दिख रहा है, जिससे इन दोनों इलाकों के बीच साफ तौर पर एक अंतर दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर उस समय की स्थिति दिखाती है जब दक्षिण-पश्चिम मॉनसून भारत के कुछ हिस्सों से लौटने की प्रक्रिया में है, जबकि वायुमंडलीय सिस्टम अलग-अलग इलाकों में बारिश पर असर डाल रहे हैं। पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादलों के बनने का संबंध नमी वाली हवाओं, कम दबाव वाले सिस्टम और अन्य वायुमंडलीय हलचलों से हो सकता है।

सिर्फ़ सैटेलाइट तस्वीर से यह पक्का नहीं किया जा सकता कि इस पैटर्न के लिए कौन सा मौसम सिस्टम जिम्मेदार है। इनसेट-3डीएस सैटेलाइट भारत के मौसम संबंधी सैटेलाइट प्रोग्राम का हिस्सा है और यह बादलों, वायुमंडलीय तापमान, नमी और मौसम से जुड़े अन्य पैमानों की जानकारी देता है।

इससे का थर्मल इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी और वायुमंडल से निकलने वाले रेडिएशन का पता लगाता है, जिससे मौसम वैज्ञानिक रात में भी बादलों के पैटर्न को देख पाते हैं। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में बादलों की स्थिति में कितना बड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग वायुमंडलीय स्थितियां देश के मौसम पर असर डालती हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

प्रकृति, संस्कृति और समाज को जोड़ता सतत पर्यटन

(लेखक - योगेश कुमार गोयल)

विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर) पर विशेष)

पर्यटन का महत्व शिक्षा और कौशल विकास के संदर्भ में भी कम नहीं है। यह न केवल यात्रियों को नई संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों से परिचित कराता है बल्कि युवाओं को आतिथ्य, प्रबंधन, संचार और सांस्कृतिक समझ जैसे कौशल सीखने के अवसर भी देता है। भारत जैसे देश, जहां युवाओं की जनसंख्या बड़ी संख्या में है, पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से विशाल रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान कर सकते हैं। छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में होम-स्टे, स्थानीय गाइड सेवा, पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प आधारित पर्यटन न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं।

पर्यटन केवल मनोरंजन, सैर-सपाटे या विश्राम का माध्यम नहीं है, यह मानव सभ्यता के विकास में निरंतर योगदान देने वाला एक ऐसा वैश्विक उद्योग है, जिसने संस्कृतियों को जोड़ा, विविधताओं को समझने का अवसर दिया और आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। 'संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन' द्वारा प्रतिवर्ष 27 सितम्बर को मनाया जाने वाला यह दिवस विश्व समुदाय को पर्यटन के बहुआयामी महत्व और इसके दूरगामी प्रभावों पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है। पर्यटन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्थान असाधारण है। वैश्विक स्तर पर यह उद्योग प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है और करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक दस में से एक नौकरी पर्यटन से जुड़ी है। विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में भी यह एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। भारत की बात करें तो यह क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत योगदान देता है और सीधे या अपरोक्ष रूप से पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। विश्व पर्यटन दिवस का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें केवल आर्थिक आंकड़ों की चमक पर नहीं बल्कि उन सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें पर्यटन उद्योग के सतत विकास के लिए प्राथमिकता देना आवश्यक है।

पर्यटन सामाजिक समानता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। जब एक यात्री किसी दूसरे देश, राज्य या संस्कृति से जुड़ता है तो यह केवल यात्रा नहीं होती बल्कि यह संवाद, सहअस्तित्व और समझदारी का अवसर बनती है। एक ओर यह यात्रियों को नए अनुभव और दृष्टिकोण प्रदान करता है तो दूसरी ओर स्थानीय समुदायों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को साझा करने का अवसर देता है। यही कारण है कि पर्यटन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पारंपरिक कलाओं, शिल्प और रीति-रिवाजों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। कई बार जो कला या परंपरा लुप्त होने के कगार पर होती है, वह पर्यटन के कारण नए जीवन का संचार प्राप्त करती है।

आधुनिक समय में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां पर्यटन के समक्ष सबसे बड़ी बाधाएं बनकर उभरी हैं। पर्यटन का अत्यधिक और अनियंत्रित विकास कई बार प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटकों का दबाव ग्लेशियरों और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल असर डालता है, समुद्र तटों पर अनियंत्रित पर्यटन समुद्री जीवन को खतरे में डालता है और ऐतिहासिक धरोहरों पर भीड़भाड़ से उनका संरक्षण कठिन हो जाता है। यही कारण है कि 'सतत पर्यटन' की अवधारणा आज सर्वाधिक चर्चा में है। सतत पर्यटन का अर्थ है ऐसा पर्यटन, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, स्थानीय समुदायों को अधिकतम लाभ मिले और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। इस दिशा में अनेक देशों ने उल्लेखनीय पहल की है। उदाहरणस्वरूप, भूटान ने पर्यटन पर 'हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम' नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत वह पर्यटकों की संख्या सीमित रखते हुए गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करता है ताकि पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संतुलन बना रहे। इसी प्रकार यूरोप के कई देशों ने 'ग्रीन टूरिज्म' मॉडल को अपनाकर पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है। भारत में भी सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

पर्यटन का महत्व शिक्षा और कौशल विकास के संदर्भ में भी कम नहीं है। यह न केवल यात्रियों को नई संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों से परिचित कराता है बल्कि युवाओं को आतिथ्य, प्रबंधन, संचार और सांस्कृतिक समझ जैसे कौशल सीखने के अवसर भी देता है। भारत जैसे देश, जहां युवाओं की जनसंख्या बड़ी संख्या में है, पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से विशाल रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान कर सकते हैं। छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में होम-स्टे, स्थानीय गाइड सेवा, पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प आधारित पर्यटन न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। पर्यटन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष शांति और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। जब विभिन्न देशों के लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं तो यह न केवल सांस्कृतिक समझ को बढ़ाता है बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग की नींव भी रखता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी पर्यटन को 'शांति का दूत' कहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ा है, आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। इसीलिए पर्यटन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग की दिशा में एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

डिजिटल तकनीक ने पर्यटन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ऑनलाइन बुकिंग, वर्चुअल टूर, एआई आधारित ट्रैवल गाइड और स्मार्ट पर्यटन समाधान ने यात्रियों के अनुभव को न केवल सरल बनाया है बल्कि अधिक सुलभ और सुरक्षित भी बनाया है। हालांकि तकनीक के उपयोग के साथ-साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। यात्रियों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। केवल सरकार या उद्योग नहीं बल्कि प्रत्येक यात्री को भी यह समझना होगा कि उसकी छोटी-सी आदतें पर्यटन को सतत और परिवर्तनकारी बनाने में योगदान कर सकती हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों है। यहां हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर केरल की बैकवाटर्स,

राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर की हरियाली, वाराणसी के घाटों से लेकर कश्मीर की वादियों तक असीमित संभावनाएं हैं लेकिन इन संभावनाओं के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी जुड़ा हुआ है। अगर पर्यटन को अनियंत्रित और असंतुलित तरीके से बढ़ने दिया गया तो यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि स्थानीय समुदायों और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रभावित करेगा। इसलिए पर्यटन विकास की हर नीति में स्थिरता और समावेशिता को प्राथमिकता देनी होगी।

पर्यटन का असली अर्थ केवल यात्रा या मनोरंजन नहीं बल्कि सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन है। जब हम पर्यटन को जिम्मेदारी से देखते हैं तो यह न केवल देशों की सीमाओं को जोड़ता है बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। यह नए अवसरों के द्वार खोलता है, समाज को अधिक समान और समावेशी बनाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सुंदर पृथ्वी छोड़ने की दिशा में प्रेरित करता है। पर्यटन का उद्देश्य केवल आज की जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। यदि हम इस उद्योग को सतत परिवर्तन का वाहक बना सके तो यह न केवल करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगा बल्कि एक बेहतर, अधिक न्यायसंगत और संतुलित दुनिया की नींव भी रखेगा। यह समय केवल पर्यटन की आर्थिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का नहीं बल्कि इसे सामाजिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग का सशक्त माध्यम बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का है।

(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तक- भारत की रक्षा क्रांति' सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

ट्रंप- जिनपिंग वार्ता

वैसे तो चमक-दमक और जोरदार मेहमाननवाजी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वॉशिंगटन में हुई मुलाकात प्रथम दृष्टया शानदार नजर आती है। लेकिन हकीकत में इस समिट का कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आया। दिल मिलें न मिलें हाथ मिलाने की तर्ज पर एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कितनी गहराई तक आपस में जुड़ी हुई हैं। उनमें गहरे मतभेद और मुखर प्रतिद्वंद्विता आज भी कायम है। वार्ता का स्पष्ट परिणाम उनके बीच व्यापारिक युद्ध विराम का आगे बढ़ना है। हालांकि, दोनों देशों के व्यापारिक मामलों को लेकर बुनियादी विवाद अभी खत्म नहीं हुए हैं। अमेरिका ने कई तरह के टैरिफ चीन पर थोपे हैं, अमेरिकी सामान का चीन द्वारा खरीदने का विवाद, रेयर-अर्थ सप्लाई और चीन को दी जाने वाली उन्नत तकनीकों पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी हैं। लेकिन दोनों देशों के कारोबारियों के लिये थोड़े समय की राहत को स्थायी समझौता नहीं माना जा सकता। हालांकि इसके बावजूद इस शिखर सम्मेलन के संकेतिक महत्व को स्वीकार करना होगा। जिस तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए रेड कॉर्पेट बिछाया गया, राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप जिस तरह परंपरा को नजरअंदाज करके हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग का स्वागत करने गए, उससे प्रतिस्पर्धी दौर में चीन के बढ़ते प्रभाव का ही पता चलता है। ट्रंप ने गर्व के साथ व्हाइट हाउस के नये रूप में तैयार परिसर को उन्हें दिखाया और शानदार राजकीय भोज का भी आयोजन किया। हालांकि, ताइवान के मामले में बहुत कुछ दांव पर लगा था। शी ने वाशिंगटन से ताइवान की आजादी का विरोध करने और इस मुद्दे को संवेदनशील ढंग से संभालने का भी आग्रह किया। जिसे चीन वक्त की समझदारी मानता है। हालांकि, अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर एक अस्पष्ट नीति को अपनाए हुए है। एक ओर अमेरिका ताइवान की अपनी रक्षा करने की नीति का समर्थन तो करता है, लेकिन उसकी संप्रभुता को औपचारिक मान्यता भी नहीं देता। सही मायने में इस बहाने शी ने डोनॉल्ड ट्रंप को चीन की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। उन्होंने अमेरिका को संकेत दिया कि चीन ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वास्तव में चीनी रणनीति का सिद्धांत उस अवधारणा पर केंद्रित है, जो टकराव के खतरे को बताती है। यह खतरा तब पैदा होता है जब कोई स्थापित शक्ति किसी उभरती शक्ति का सामना करती है। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने मौजूदा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच सैन्य बातचीत की अपरिहार्यता को बताया। साथ ही किसी भी तरह के संकट को टालने के लिये मजबूत तंत्र बनाने का भी आह्वान किया। निस्संदेह, इस तरह की पहल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजिंग और वाशिंगटन के मध्य असहमति केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों तक विस्तृत है। सही मायने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता खोज हेतु जारी तीव्र होड़ ने इस अंतर को दर्शाया है। आज बेहद तेजी से विकसित होती एआई तकनीक को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं पैदा हुई हैं। दुनिया में एआई के शोध-अनुसंधान की गति को धीमा करने की मांग की जा रही है ताकि मानवता के लिये नया संकट पैदा न हो। एक ओर ट्रंप ने एआई को नियमों से बचाने पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर शी जिनपिंग ने तर्क दिया कि एआई को इंसानी नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। इसकी भूमिका सिर्फ मानव हित में काम करने तक ही सीमित रहनी चाहिए। दो महाशक्तियों में एआई को लेकर भिन्न-भिन्न नजरिये से स्पष्ट होता है कि भविष्य में इस क्षेत्र में सहयोग शायद मुश्किल होगा।

टकराव के बीच अमेरिका- चीन मिलन के कूटनीतिक समझौते

(लेखक- सौरभ वार्ष्णेय)

विश्व राजनीति में अमेरिका और चीन के संबंध इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां टकराव और संवाद दोनों साथ-साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ओर दोनों देश व्यापार, तकनीक, ताइवान, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक प्रभाव के विस्तार को लेकर एक-दूसरे के सामने खड़े हैं, तो दूसरी ओर आर्थिक हित उन्हें बातचीत की मेज पर भी ला रहे हैं। यही विरोधाभास आज के बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी तस्वीर है। अमेरिका और चीन की हालिया नजदीकी को केवल मित्रता के रूप में देखना जितना गलत होगा, उतना ही इसे महज दिखावटी कूटनीति मान लेना भी उचित नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि दोनों महाशक्तियां यह समझ रही हैं कि लगातार बढ़ता टकराव किसी एक पक्ष के हित में नहीं है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने का असर केवल वाशिंगटन और बीजिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखलाओं, निवेश और विकास की गति पर पड़ता है। यही कारण है कि तीखे बयानों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रखे जा रहे हैं। अमेरिका अपनी आर्थिक और तकनीकी बढ़त को सुरक्षित रखना चाहता है, जबकि चीन अपने औद्योगिक विस्तार, निर्यात बाजार और तकनीकी विकास के लिए स्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण चाहता है। दोनों के हितों में टकराव है, लेकिन उनकी आर्थिक आवश्यकताएं उन्हें एक-दूसरे से पूरी तरह अलग होने की अनुमति नहीं देतीं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है। तकनीक इस संघर्ष का नया केंद्र बन चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत विनिर्माण और दुर्लभ खनिज जैसे क्षेत्र अब आर्थिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका चीन की तकनीकी क्षमता और औद्योगिक विस्तार को लेकर सतर्क है, वहीं चीन अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों को अपने विकास के रास्ते में बाधा के रूप में देखता है।

इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत का जारी रहना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों के बीच रणनीतिक अविश्वास समाप्त हो गया है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि दोनों देश अपने मतभेदों को नियंत्रित रखने और उन क्षेत्रों में समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां परस्पर हित जुड़े हुए हैं। ताइवान का मुद्दा इस रिश्ते की सबसे संवेदनशील परीक्षा है। व्यापार और आर्थिक मामलों में समझ विकसित हो सकती है, लेकिन ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की रणनीतिक सोच में मूलभूत अंतर मौजूद है। इसी तरह दक्षिण चीन सागर, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक प्रभाव के विस्तार को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद आसानी से समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए वर्तमान नजदीकी को स्थायी दोस्ती की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी।

असल में अमेरिका और चीन के संबंधों में एक नई तरह की कूटनीति दिखाई दे रही है । प्रतिस्पर्धा के साथ सह-अस्तित्व की कूटनीति। दोनों देश एक-दूसरे के प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण टकराव से भी बचना चाहते हैं। वे व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन रणनीतिक निर्भरता कम करना चाहते हैं। वे संवाद चाहते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।यही स्थिति आने वाले समय की विश्व राजनीति को भी प्रभावित करेगी। यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव नियंत्रित रहता है तो वैश्विक बाजारों को कुछ स्थिरता मिल सकती है। इसके विपरीत यदि शुल्क युद्ध फिर तेज होता है तो उसका असर विकासशील देशों पर भी पड़ेगा। महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत के लिए इस बदलते समीकरण को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, वहीं चीन भारत का पड़ोसी और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में भारत के लिए किसी एक शक्ति-गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका और चीन के बीच यदि तनाव कम होता है तो भारत के लिए वैश्विक आर्थिक स्थिरता का वातावरण बन सकता है। वहीं यदि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है तो भारत के सामने विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश के क्षेत्र में अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इन अवसरों को हासिल करने के लिए भारत को अपनी उत्पादन क्षमता, तकनीकी दक्षता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना होगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और चीन की यह नजदीकी कितने समय तक टिकती है। क्या यह वास्तविक समझ की दिशा में कदम है या केवल तत्काल आर्थिक दबावों को कम करने की रणनीति? इसका उत्तर आने वाला समय देगा। दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनना आसान नहीं है। इसलिए किसी एक बैठक या अस्थायी समझौते को स्थायी परिवर्तन का संकेत मानना उचित नहीं होगा। फिर भी एक बात स्पष्ट है आज की दुनिया में महाशक्तियां भी एक-दूसरे से पूरी तरह कटकर नहीं चल सकतीं। आर्थिक परस्पर निर्भरता, वैश्विक व्यापार, तकनीकी विकास और साझा चुनौतियां उन्हें संवाद के लिए मजबूर करती हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव के बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी है।

अमेरिका और चीन की वर्तमान नजदीकी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि विश्व राजनीति अब केवल शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि शक्ति और आवश्यकता के संतुलन से संचालित हो रही है।दोनों देश प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन एक-दूसरे की आर्थिक और वैश्विक भूमिका की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए इस नजदीकी को दोस्ती या दुश्मनी के पुराने पैमाने पर देखने के बजाय बदलती विश्व व्यवस्था के संकेत के रूप में समझना चाहिए। आने वाले वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों का स्वरूप वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारकों में रहेगा। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह इस बदलते समीकरण में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए आर्थिक और कूटनीतिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाए।

चिंतन मनन

प्रयत्न में ऊब नहीं

संसार में गति के जो नियम हैं, परमात्मा में गति के ठीक उनसे उलटे नियम काम आते हैं और यहीं बड़ी मुश्किल हो जाती है। संसार में ऊबना बाद में आता है, प्रयत्न में ऊब नहीं आती। इसलिए संसार में लोग गति करते चले जाते हैं। पर परमात्मा में प्रयत्न में ऊब आती है और प्रयत्न पहले ही उबा देगा, तो आप रुक जाएंगे। कितने लोग हैं जो प्रभु की यात्रा शुरू भर करते हैं, पर कभी पूरी नहीं कर पाते। कितनी बार तय किया कि स्मरण कर लेंगे प्रभु का घड़ीभर! एकाध दिन, दो दिन। फिर ऊब गए। फिर छूट गया। कितने संकल्प, कितने निर्णय, धूल होकर पड़े हैं चारों तरफ! लोग कहते हैं कि ध्यान से कुछ हो सकेगा? मैं कहता हूं जरूर हो सकेगा। कठिनाई सिर्फ एक है, सातत्य! कितने दिन कर सकोगे? मुश्किल से कोई मिलता है, जो तीन महीने भी सतत कर पाता है। दस-पांच दिन बाद ऊब जाता है! आश्चर्य है कि मनुष्य जिंदगी भर अखबार पढ़कर नहीं ऊबता, रेडियो सुनकर नहीं ऊबता, फिल्म देखकर नहीं ऊबता, रोज वही बातें करके नहीं ऊबता। ध्यान करके क्यों ऊब जाता है? आखिर ध्यान में ऐसी क्या कठिनाई है! कठिनाई एक ही है कि संसार की यात्रा पर प्रयत्न नहीं उबाता, प्राप्ति उबाती है और परमात्मा की यात्रा पर प्रयत्न उबाता है, प्राप्ति कभी नहीं उबाती। जो पा लेता है, वह फिर कभी नहीं ऊबता। बुद्ध ज्ञान के बाद चालीस साल जिंदा थे।

चालीस साल किसी ने एक बार उन्हें अपने ज्ञान से ऊबते हुए नहीं देखा। कोहनूर हीरा मिल जाता चालीस साल तो ऊब जाते। संसार का राज्य मिल जाता तो ऊब जाते। महावीर भी चालीस साल जिंदा रहे ज्ञान के बाद। निरंतर उसी ज्ञान में रमे रहे, कभी ऊबे नहीं! कभी चाहा नहीं कि कुछ और मिल जाए। परमात्मा की यात्रा पर प्राप्ति के बाद कोई ऊब नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि बिना ऊबे श्रम करना कर्त्तव्य है, करने योग्य है। अर्जुन कैसे माने और क्यों माने? अर्जुन तो जब प्रयास करेगा, तो ऊबेगा, थकेगा। कृष्ण कहते हैं, इसलिए धर्म में ट्रस्ट का, भरोसे का एक कीमती मूल्य है। श्रद्धा का अर्थ होता है, ट्रस्ट। उसका अर्थ होता है, कोई कह रहा है। अर्जुन भलीभांति कृष्ण को जानता है। कृष्ण को भी विचलित नहीं देखा है। कृष्ण को उदास नहीं देखा है। कृष्ण की बांसुरी से कभी दुख का स्वर निकलते नहीं देखा है। कृष्ण सदा ताजे हैं।

निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता कठघरे में

(लेखक- विनोद कुमार उपाध्याय)

लोकतंत्र में चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं है। यह उस भरोसे का नाम है, जिसके आधार पर एक नागरिक यह मानता है कि उसका वोट सुरक्षित है, मतदाता सूची में उसका नाम निष्पक्ष तरीके से दर्ज है और चुनाव कराने वाली संस्था किसी दबाव, पक्षपात या मनमानेपन से मुक्त होकर काम कर रही है। इसलिए निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर उठने वाला हर सवाल महज राजनीतिक विवाद नहीं होता। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा प्रश्न बन जाता है। हाल में निर्वाचन आयोग के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी के बीच कथित मतभेदों को लेकर सामने आई रिपोर्टों ने इसी कारण असामान्य चिंता पैदा की है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने पिछले दस महीनों में आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें नए मतदाताओं के पंजीयन, मतदाता सूची से नाम हटाने, चुनावी डेटा तक पहुंच और आईटी व्यवस्था जैसे गंभीर विषय शामिल बताए गए हैं। आयोग ने दूसरी ओर इन मतभेदों की व्याख्या अलग तरीके से की है और कहा है कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से हुए तथा ऐसी टिप्पणियां विचार-विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा थीं। यही वह बिंदु है जहां से असली सवाल पैदा होता है—यदि सब कुछ सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है तो फिर उन आपत्तियों, उनके जवाब और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से स्पष्ट क्यों न हो? यहां किसी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्हें केवल राजनीतिक आरोप कहकर खारिज कर देना भी पर्याप्त नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का सबसे मजबूत आधार यही है कि वह कठिन सवालों का सामना तथ्यों और दस्तावेजों के साथ करें। सबसे गंभीर प्रश्न मतदाता सूची से जुड़ा है। चुनाव में उम्मीदवार हार-जीत सकता है, राजनीतिक दल सत्ता में आ-जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम न होना सीधे उसके संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दो निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता पंजीयन के फॉर्म-6 में किए गए बदलाव पर आपत्ति दर्ज की थी। उनका तर्क था कि वैधानिक प्रावधानों से जुड़े फॉर्म में बदलाव के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीक और डिजिटल व्यवस्था अब चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मतदाता सूची का डिजिटल प्रबंधन सुविधा बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ जवाबदेही भी उतनी ही बढ़नी चाहिए। यदि किसी स्तर पर सॉफ्टवेयर किसी अधिकारी के निर्णय को स्वीकार नहीं करता, किसी योग्य मतदाता का नाम अटक जाता है या केंद्रीय स्तर की तकनीकी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर लिए गए वैधानिक निर्णय को प्रभावित करती है, तो उसके लिए स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए। रिपोर्ट में गोवा के 97 मतदाताओं से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें स्थानीय स्तर पर पात्रता स्वीकार किए जाने के बावजूद सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या का उल्लेख किया गया। यही वजह है कि चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी गलती जैसे शब्द भी हल्के में नहीं लिए जा सकते। बैंकिंग व्यवस्था में गलत खाते में पैसा चला जाए तो उसे तकनीकी त्रुटि कहा जा सकता है और सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन चुनाव में किसी योग्य नागरिक का वोट देने का अवसर निकल जाए तो वह गलती अगले चुनाव तक सुधरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। चुनावी अधिकार समयबद्ध होता है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी यही कसौटी लागू होनी चाहिए। मतदाता सूची को साफ-सुथरा और अद्यतन रखना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। मृत, स्थानांतरित, दोहराए गए या अपात्र नाम हटाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है। लेकिन वैध मतदाता का नाम हटने की आशंका भी उतनी ही गंभीर है। पश्चिम बंगाल के मामले में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एसआईआर के दौरान हटाए गए 27.16 लाख नामों में से 22 लाख से अधिक मतदाताओं ने बहाली के लिए अपील की। इस आंकड़े का अर्थ यह नहीं कि हर हटाया गया नाम सही था या हर अपील स्वीकार की जानी चाहिए। इसका सीधा अर्थ केवल इतना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ एक मजबूत, आसान और समयबद्ध अपील व्यवस्था भी अनिवार्य है। नागरिक को यह पता होना चाहिए कि उसका नाम क्यों हटाया गया, निर्णय किस अधिकारी ने लिया, उसके पास कौन-से दस्तावेज होने चाहिए और उसकी शिकायत का अंतिम निपटारा कब तक होगा। निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद का मुद्दा भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तीन सदस्यीय आयोग में असहमति अपने आप में लोकतंत्र विरोधी बात नहीं है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

नाटको फार्मा जुटाएगी 1279 करोड़

कंपनी 750 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी करेगी 1.70 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर

नई दिल्ली ।

दवा कंपनी नाटको फार्मा ने पूंजी जुटाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने राइट इश्यू के माध्यम से अधिकतम 1,279.35 करोड़ रुपये जुटाने को अपनी मंजूरी दे दी है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी 750 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2 रुपये अंकित मूल्य वाले अधिकतम 1,70,58,082 इक्विटी शेयर जारी करेगी। इस राइट इश्यू का उद्देश्य कंपनी के वित्तीय विस्तार को मजबूती देना है। पात्र शेयरधारकों के लिए रिकॉर्ड तारीख 1 अक्टूबर तय की गई है। इसके तहत, निवेशकों को उनके पास मौजूद प्रत्येक 21 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों पर दो नए शेयर दिए जाएंगे। यह राइट इश्यू 12 अक्टूबर को खुलेगा और 22 अक्टूबर को बंद होगा। शेयरधारक 12 से 16 अक्टूबर के बीच अपने राइट को बाजार में किसी अन्य को हस्तांतरित या बेच भी सकेंगे। बोर्ड ने आचार संहिता में संशोधन को भी मंजूरी दी।

वाहन परीक्षण बुनियादी ढांचा उन्नयन के लिए 780 करोड़ आवंटित- मंत्री

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने आईसीएटी20 कार्यक्रम में की घोषणा

नई दिल्ली ।

केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने घोषणा की कि मंत्रालय ने देश भर की सभी वाहन परीक्षण एजेंसियों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह आवंटन भारत के तेजी से बदलते वाहन क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री कुमारस्वामी मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) में आयोजित आईसीएटी20 - उत्कृष्टता के 20 वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम वाहन परीक्षण, प्रमाणन और औद्योगिक विकास में आईसीएटी के दो दशकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन, वैकल्पिक ईंधन और स्मार्ट परिवहन जैसे नवाचार भारतीय वाहन उद्योग को नया आकार दे रहे हैं। इस बदलते परिदृश्य में, उन्होंने मजबूत और आधुनिक परीक्षण अवसंरचना की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके लिए सरकार यह व्यापक निवेश कर रही है ताकि देश की परीक्षण क्षमताओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत किया जा सके।

आईपीओ बाजार में एडरॉयट सहित चार इश्यू हुए ओवरसब्सक्राइब

एडरॉयट इंडस्ट्रीज के आईपीओ को मिला 177 गुना बंपर अभिदान,

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जब शुक्रवार को चार कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बंपर अभिदान के साथ बंद हुए। इनमें एडरॉयट इंडस्ट्रीज का आईपीओ सबसे आगे रहा, जिसे अंतिम दिन करीब 177 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्वास्तिका इंफ्रा, एलिवेट कैम्पसेज और आरमी इंफोटेक के आईपीओ को भी निवेशकों का मजबूत समर्थन मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 151 करोड़ रुपये के एडरॉयट इंडस्ट्रीज के आईपीओ में 78,72,900 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 1,39,22,95,200 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जिससे यह 176.85 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। इस आईपीओ को गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से 332.35 गुना, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की ओर से 195.04 गुना और खुदरा निवेशकों की ओर से 99.81 गुना अभिदान मिला। इसका मूल्य दायरा 126-134 रुपये प्रति शेयर था। अन्य आईपीओ में, विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधाएं और स्कूली शिक्षा से जुड़ी कंपनी एलिवेट कैम्पसेज के 2,100 करोड़ रुपये के आईपीओ को 1.79 गुना अभिदान मिला। वहीं स्वास्तिका इंफ्रा के 161 करोड़ रुपये के आईपीओ को 7.60 गुना और आरमी इंफोटेक के आईपीओ को 2.44 गुना अभिदान प्राप्त हुआ, जो भारतीय आईपीओ बाजार में बढ़ती निवेशक रुचि को दर्शाता है।

वैश्विक चिंताओं के चलते लगातार 7वें सप्ताह फिसला बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी 0.88 प्रतिशत तक टूटा

मुंबई।

वैश्विक चिंताओं के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार सातवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के कारण प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में 0.88 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की ग सासाहिक आधार पर निफ्टी 0.88 प्रतिशत कमजोर हुआ, हालांकि सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन इसमें 0.34 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह 23,140 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स शुक्रवार को 315 अंक यानी 0.43 प्रतिशत चढ़कर 73,895 पर बंद हुआ, लेकिन पूरे सप्ताह में इसमें 0.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गुरुवार को दोनों प्रमुख सूचकांक 1.6 प्रतिशत से ज्यादा टूट गए थे, जबकि शुक्रवार को चुनिंदा शेयरों में वैल्यू बाइंग के चलते सीमित रिकवरी देखने को मिली।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सप्ताह भर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहीं, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार करता रहा। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंताओं ने तेल बाजार को सहारा दिया। हालांकि सप्ताह के अंत में तेल कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली, जिससे आयात बिल, महंगाई, रुपए और कॉरपोरेट लागत पर दबाव की आशंकाएं थोड़ी कम हुईं। दूसरी ओर, अमेरिकी बॉन्ड बाजार ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई। अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड सप्ताह के दौरान 5.10 प्रतिशत के ऊपर पहुंच गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंची यील्ड वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों को सख्त बनाती है और उभरते बाजारों की परिसंपत्तियों को अपेक्षाकृत कम आकर्षक बना सकती है।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी बाजार के लिए बड़ी चुनौती बनी रही। एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई लगातार छठे सप्ताह शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने सप्ताह के दौरान 11,490 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखते हुए 16,398 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया, जिससे बाजार में गिरावट कुछ हद तक सीमित रही। सितंबर महीने में अब तक एफआईआई कुल 18,531 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जबकि डीआईआई ने 52,617 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है।

इसके बावजूद निफ्टी अगस्त के अंत के स्तर से लगभग 3.9 प्रतिशत नीचे बना हुआ है। बाजार की नजरें अब पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी टिकी हैं।

फ्लेक्सी कैप फंड- लंबी अवधि का प्रदर्शन क्यों है अहम?

बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच निवेश का लचीला विकल्प

नई दिल्ली ।

शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच फ्लेक्सी कैप फंड निवेशकों के बीच चर्चा में हैं। ये फंड मैनेजरों को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बड़ी, मझोली और छोटी कंपनियों में निवेश का अनुपात बदलने की सुविधा देते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ एक साल के रिटर्न को देखकर इन फंडों में निवेश का फैसला लेना ठीक नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के प्रदर्शन और जोखिम को समझना आवश्यक है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने एक साल में 10.77 फीसदी का रिटर्न दिया, लेकिन तीन साल में 19.35 फीसदी और पांच साल में 16.39 फीसदी का प्रभावशाली रिटर्न दिखाया। वहीं, क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट का एक साल का रिटर्न 10.22 फीसदी था, जबकि लंबी अवधि में यह भी बेहतर रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन में अंतर हो सकता है। बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के अनुसार फ्लेक्सी कैप जैसे डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड का आकलन तीन से पांच साल की अवधि में करना अधिक उपयोगी है। केवल पॉइंट-टू-पॉइंट के बजाय रोलिंग रिटर्न भी देखना चाहिए। फंड चुनते समय जोखिम-समायोजित रिटर्न (जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन) पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही, फंड की निवेश शैली, मार्केट कैप में हिस्सेदारी और किसी एक सेक्टर या शेयर में अत्यधिक एकाग्रता भी देखनी चाहिए।

डीएचएल एक्सप्रेस बढ़ाएगी माल ढुलाई शुल्क

नए साल से 8.9 फीसदी महंगा होगा शिपमेंट

मुंबई ।

प्रमुख लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता डीएचएल एक्सप्रेस ने घोषणा की है कि वह अगले साल 1 जनवरी से भारत में अपनी माल ढुलाई शुल्क में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। कंपनी ने इस वार्षिक शुल्क वृद्धि के पीछे बढ़ती मुद्रास्फीति, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और उद्योग-विशिष्ट लागतों में वृद्धि जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। डीएचएल एक्सप्रेस ने स्पष्ट किया कि 220 से अधिक देशों और क्षेत्रों में परिचालन करने के कारण, वह न केवल स्थानीय आर्थिक स्थितियों बल्कि वैश्विक बाजारों के घटनाक्रमों से भी प्रभावित होती है। कंपनी के अनुसार, उसकी लागत संरचना ऊर्जा खर्च, अनुपालन आवश्यकताओं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा लागू किए जाने वाले बदलते सीमा शुल्क से भी लगातार प्रभावित हो रही है, जिसके चलते यह वृद्धि आवश्यक हो गई है। डीएचएल एक्सप्रेस के दक्षिण एशिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस सुब्रमण्यन ने इस समायोजन को सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह वार्षिक मूल्य समायोजन हमें सेवा और विश्वसनीयता के उस उच्च स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जिसकी हमारे ग्राहक अपेक्षा करते हैं। साथ ही यह हमारे वैश्विक परिचालन के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को भी मजबूत करता है। सुब्रमण्यन ने यह भी दोहराया कि कंपनी अपने ग्राहकों को बदलते कारोबारी परिवेश में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वैश्विक नेटवर्क, डिजिटल क्षमताओं, सुरक्षा बुनियादी ढांचे और टिकाऊ लॉजिस्टिक समाधानों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेवानिवृत्ति की योजना- सिर्फ कॉर्पस नहीं,समग्र रणनीति पर दें जोर

महंगाई, मेडिकल खर्च और लंबी उम्र को ध्यान में रखकर बनाएं ठोस रणनीति

नई दिल्ली ।

सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय केवल एक बड़ा कॉर्पस बनाने का लक्ष्य रखना अपर्याप्त हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद 20 से 30 साल या उससे अधिक के जीवनकाल के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक समग्र और दूरदर्शी रणनीति अपनाना अनिवार्य है। महंगाई, स्वास्थ्य व्यय और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न जैसे कई कारक आपकी भविष्य की जरूरतों को प्रभावित करते हैं, जिनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है। रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल एक निश्चित कॉर्पस राशि तय कर देना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले यह अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आपकी जीवनशैली और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। भले ही नौकरी के दौरान के कुछ खर्च, जैसे आने-जाने और काम से जुड़े व्यय कम हो जाएं, वहीं स्वास्थ्य देखभाल, यात्रा, शौक और परिवार की मदद जैसे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। भविष्य में आज की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त लगने वाली रकम महंगाई के कारण कम न पड़े, इसके लिए महंगाई दर को भी योजना में शामिल करना अनिवार्य है। वित्तीय जानकारों के मुताबिक, रिटायरमेंट के लिए निवेश जितनी जल्दी शुरू किया जाए, कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) का उतना ही अधिक लाभ मिलता है, जिससे लक्ष्य हासिल करने के लिए मासिक योगदान अपेक्षाकृत कम रहता है। नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे विकल्प लंबे समय तक नियमित योगदान का अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ ही, औसत आयु में वृद्धि को देखते हुए, रिटायरमेंट के बाद कम से कम 25 से 35 साल के खर्च की योजना बनाना विवेकपूर्ण है। जीवनसाथी और आश्रितों की जरूरतों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। पेंशन, किराये, ब्याज या एन्युटी से होने वाली अन्य आय को भी गणना में जोड़कर निवेश से अपेक्षित अतिरिक्त आय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। यह भी जरूरी है कि सेवानिवृत्ति योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाए। आय, खर्च या निवेश की स्थिति में बदलाव आने पर योगदान राशि या रणनीति में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। केवल कॉर्पस बनाना ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उस राशि को बुद्धिमानी से निकालने की योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

शुरुआती वर्षों में आवश्यकता से अधिक निकासी से फंड पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, निवेश और निकासी पर लागू होने वाले कर नियमों को समझना भी अनिवार्य है।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई एक सुनियोजित रणनीति सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती है।

भारत में एफडीआई 6 फीसदी बढ़ा, जापान शीर्ष पर, अमेरिकी निवेश 76 फीसदी घटा

अप्रैल-जून तिमाही में कुल 19.81 अरब डॉलर का सीधा विदेशी निवेश

नई दिल्ली ।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) छह प्रतिशत बढ़कर 19.81 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान जापान 5.71 अरब डॉलर के साथ सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा, जबकि अमेरिका से आने वाले एफडीआई में 76 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। डीपीआईआईटी के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल एफडीआई (इक्विटी निवेश, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी सहित) इस तिमाही में 22 प्रतिशत बढ़कर 30.65 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि, तिमाही के भीतर मई और जून में मासिक एफडीआई में गिरावट देखी गई, जिसे अप्रैल में हुए दोगुने निवेश (12.1 अरब डॉलर) ने संतुलित किया। जापान के बाद सिंगापुर (5.22 अरब डॉलर) और मॉरीशस (2.31

अरब डॉलर) प्रमुख निवेशकों में शामिल रहे। अमेरिका से एफडीआई घटकर 1.34 अरब डॉलर रह गया, वहीं संयुक्त अरब अमीरात से भी निवेश में कमी आई।

प्रमुख क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र को सर्वाधिक 7.04 अरब डॉलर का एफडीआई मिला, इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर (2.84 अरब डॉलर) और व्यापार क्षेत्र प्रमुख रहे। राज्यों में, तमिलनाडु 5.95 अरब डॉलर के साथ एफडीआई आकर्षित करने में शीर्ष पर रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र (4.22 अरब डॉलर) और दिल्ली (2.67 अरब डॉलर) का स्थान रहा।

ऑडी इंडिया ने छत्रपति संभाजीनगर संयंत्र में क्यू3 मॉडल का उत्पादन शुरू किया

छत्रपति संभाजीनगर संयंत्र में असेंबली शुरू, 16 अक्टूबर को होगी लॉन्चिंग

छत्रपति संभाजीनगर ।

जर्मन लग्जरी वाहन निर्माता ऑडी ने भारत में अपनी लोकप्रिय एसयूवी क्यू3 का स्थानीय उत्पादन शुरू कर दिया है। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय ग्राहकों को जल्द ही यह बहुप्रतीक्षित लग्जरी एसयूवी उपलब्ध होगी। ऑडी क्यू3 का उत्पादन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के शेंद्रा संयंत्र में शुरू किया गया है। कंपनी ने घोषणा की है कि नई ऑडी क्यू3 को भारत में 16 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। यह मॉडल 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और ऑडी के प्रसिद्ध क्वात्रो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस होगा, जिसमें अपनी श्रेणी के कुछ विशेष फीचर और अत्याधुनिक तकनीकें भी शामिल होंगी। स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पीयूष अरोड़ा ने इस उत्पादन को कंपनी की विनिर्माण क्षमता का परिचायक बताया। ऑडी इंडिया के एक अे धिकारी ने कहा कि क्यू3 ऑडी ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल रहा है, और नई पीढ़ी के मॉडल में डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत 2.88 लाख करोड़ बढ़ी

मंत्रालय की अगस्त 2026 की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली ।

देश में 150 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 1,731 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में 2,88,122 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की अगस्त 2026 की मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत 30.71 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब संशोधित होकर 33.60 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की निगरानी में चल रही इन परियोजनाओं पर अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो संशोधित कुल लागत का 48.59 प्रतिशत है। कुल 647 परियोजनाओं में 80 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जबकि 312 में इतनी ही वित्तीय प्रगति हुई है। परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में सर्वाधिक 1,191 परियोजनाएं हैं, जिनकी संशोधित लागत 16.05 लाख करोड़ रुपए है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास सबसे अधिक 982 परियोजनाएं (संशोधित लागत 9.52 लाख करोड़ रुपए) हैं।

इसके बाद रेल मंत्रालय (147 परियोजनाएं, 3.14 लाख करोड़ रुपए) और कोयला मंत्रालय (122 परियोजनाएं, 2.22 लाख करोड़ रुपए) का स्थान है। मंत्रालय ने बताया कि बड़ी संख्या में परियोजनाएं या तो शुरुआती चरण में हैं या पूरा होने के करीब हैं।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने हफ्ते भर बिगाड़ी बाजार की चाल

तेजी से गिरावट तक का सफरः भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा रहा सप्ताह

मुंबई ।

बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। जहां सप्ताह की शुरुआत मजबूत संकेतों और निवेशकों के उत्साह के साथ हुई, वहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक चिंताओं ने बाजार की चाल बिगाड़ दी, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सूचकांकों में सप्ताह के अंत तक तेज गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों की पूंजी पर अनिश्चितता के बादल छाए रहे और सप्ताह का समापन लाल निशान में हुआ। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को उत्साहजनक रही। शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांकों ने जोरदार बढ़त दर्ज की, जहां बीएसई सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़कर 74,700 के करीब पहुंचा। दिनभर की तेजी के बाद सेंसेक्स 564.03 अंक बढ़कर 74,858.99 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी भी 67.90 अंक की वृद्धि के साथ 23,414.30 के स्तर पर पहुंच गया। मंगलवार को भी बाजार ने मजबूत शुरुआत की, सेंसेक्स 101.79 अंक और निफ्टी 37.46 अंक की बढ़त के साथ खुले, लेकिन यह तेजी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आईटी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बिकवाली के दबाव से बाजार शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 329.91 अंक टूटकर 74,529.08 पर और निफ्टी 85.30 अंक गिरकर 23,329 पर आ गया। सप्ताह के सबसे बड़े झटके के तौर पर गुरुवार का दिन रहा, जब भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के महत्वपूर्ण स्तर को पार करना इस बिकवाली का मुख्य कारण रहा। वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारतीय इक्विटी बाजार भी इससे प्रभावित हुआ। बिकवाली के भारी दबाव के चलते बीएसई सेंसेक्स 1,247.71 अंक की रिकॉर्ड गिरावट के साथ 73,580.54 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 383.70 अंक फिसलकर 23,063.10 के स्तर पर आ गया। शुक्रवार को वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच बाजार में हल्की रिकवरी देखने को मिली।

बैंक हड़ताल से गहराया संकट, पांच दिनों तक बैंकिंग ठप रहने का खतरा

आठ लाख बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल 28 सितंबर से, 5-डे बैंकिंग और पेंशन मुख्य मुद्दे

मुंबई ।

देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल 5-डे बैंकिंग और पेंशन जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर बुलाई गई है। चिंता इसलिए भी गहरी हो गई है क्योंकि 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण यह सीधे तौर पर पांच दिनों के बैंकिंग अवकाश में तब्दील हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को 27 सितंबर, रविवार को भी खुले रखने का आदेश दिया है ताकि जनता के जरूरी काम निपटाए जा सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते हैं। रोजाना लाखों करोड़ रुपये का वित्तीय लेन-देन बैंकों के माध्यम से होता है। अकेले डिजिटल पेमेंट मोड जैसे यूपीआई से ही देश में हर दिन करीब 88,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का लेन-देन होता है। इसमें चेक क्लियरेंस, आरटीजीएस, एनईएफटी, सरकारी ट्रेजरी और बड़े बिजनेस लोन से जुड़ा कामकाज भी शामिल कर लिया जाए, तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीन दिनों की इस हड़ताल से भारतीय बाजार को कई मोर्चों पर भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। लगभग 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के चेक अटक सकते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों का वर्किंग कैपिटल फंस जाएगा और बाजार में नकदी के प्रवाह में बाधा आएगी।

हड़ताल के दौरान कैश जमा-निकासी, चेक क्लियरिंग, सरकारी ट्रेजरी ऑपरेशन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन और मनी मार्केट ऑपरेशन जैसी सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि यह सभी काम मुख्य रूप से ब्रांच स्टाफ पर निर्भर करते हैं। हालांकि, निजी बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ऐ क्सिस बैंक इस हड़ताल का हिस्सा नहीं होंगे, जिससे वहां कामकाज सामान्य बना रहेगा।

कैट ने नो यूपीआई डे के आह्वान की खबरों का खंडन किया

व्यापारिक संगठन ने 2 अक्टूबर को देशव्यापी बंद की खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत बताया

नई दिल्ली ।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि संगठन ने 2 अक्टूबर को देशव्यापी नो यूपीआई डे का आह्वान किया है। कैट ने एक बयान जारी कर इन खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार दिया, जिससे संगठन के रुख को लेकर पैदा हुए भ्रम को दूर किया जा सके।

संगठन ने स्पष्ट किया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में कैट द्वारा नो यूपीआई डे की घोषणा की बात कही जा रही थी। कैट ने कहा, ये खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं तथा कैट के आधिकारिक रुख को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

कैट ने यह भी बताया कि एमडीआर के मुद्दे पर कुछ अन्य व्यापारिक संगठन या क्षेत्रीय निकाय स्वतंत्र रूप से विरोध प्रदर्शन या कार्यक्रम की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कैट से जोड़ना या उसके नाम से बताना अनुचित होगा। उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर से व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) यूपीआई भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा, जिसका भुगतान व्यापारी करेंगे, बशर्ते लेनदेन 2,000 रुपए से अधिक हो। 75,000 रुपए या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल

यहां हमेशा होती रहती है बारिश

अपनी धरती पर बड़े-बड़े जंगल हैं, जहां हजारों तरह के पेड़-पौधे हैं और हजारों तरह के जीव रहते हैं। ऐसा ही एक घना जंगल है अफ्रीका महादेश के मध्य में। कांगो देश से जुड़ा यह जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है, इस कारण इसे कांगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है।

- कांगो रेन फॉरेस्ट मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह 23 लाख 45 हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है। अपना देश भारत लगभग 32 लाख 87 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी अपने देश के लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर है यह जंगल।
- यह रेन फॉरेस्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जहां खूब बारिश होती है। यहां औसतन 58 इंच बारिश हर वर्ष होती है। पहले नम्बर पर अमेजन रेनफॉरेस्ट है, जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यानी अपने देश के क्षेत्रफल से डेढ़ गुना ज्यादा क्षेत्र में है अमेजन का जंगल।
- कांगो रेन फॉरेस्ट का ज्यादा हिस्सा कांगो देश में आता है, जो अफ्रीका महादेश के मध्य में स्थित है। इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। संक्षेप में इस देश को डीआरसी भी कहा जाता है और डीआर कांगो भी।
- इस घने जंगल का काफी हिस्सा ऐसा है, जहां अब तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। यहां तक कि इस जंगल में रहने वाले लोग भी काफी बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन घने हिस्सों में सूर्य की एक प्रतिशत रोशनी ही जमीन तक पहुंच पाती है।
- इस जंगल में रहने वाले लोगों को पिग्मी कहा जाता हैं। यहां के पुरुषों की औसत लंबाई 4 फीट 10 इंच होती है, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 4 फीट 1 इंच होती है।
- इस जंगल में पांच नेशनल पार्क हैं, जिन्हें यूएन विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। यानी यह जंगल दुनिया भर के लिए बहुत महत्व रखता है।
- इस जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। यह नदी कांगो देश के अलावा कई और देशों से होकर गुजरती है। इसे दुनिया की सबसे गहरी नदी का दर्जा प्राप्त है।
- इस जंगल में 2000 से भी अधिक तरह के जीव रहते हैं। इनमें 450 से अधिक ऐसे जीव रहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। 300 से अधिक रेंगने वाले जीव रहते हैं, जैसे कीड़े-मकोड़े, सांप आदि। 200 से अधिक तरह के ऐसे जीव रहते हैं, जो पानी और उसके बाहर दोनों जगह रह सकते हैं। एक हजार से अधिक तरह की चिड़ियां इस जंगल में रहती हैं।
- इस जंगल को दुनिया का अकेला जंगल माना जाता है, जहां तीनों तरह के गुरिल्ला रहते हैं। इस जंगल में बोनोबो भी रहते हैं, जिनके बारे में कहा और माना जाता है कि यह हमसे सबसे अधिक मिलता-जुलता है।
- यह जंगल 11 हजार से भी अधिक तरह के पौधों का घर है। इनमें से एक हजार से भी अधिक प्लांट सिर्फ इसी जंगल में होते हैं।

इस सेंक्चुरी में संरक्षित रखे जाते हैं गधे

तुमने बाघ, शेर, चिड़ियों और गैंडों को बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सेंक्चुरी बनाने का बात तो सुनी होगी! पर क्या तुम्हें पता है कि भारत में एक ऐसी सेंक्चुरी है, जो जंगली गधों के लिए संरक्षित है? यह सेंक्चुरी बनाई गई है गुजरात के कच्छ में। यह इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी करीब पांच हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसीलिए यह भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है। गुजरात में इन जंगली गधों को घुड़खर कहा जाता है। ये कद में आम गधों से ऊंचे होते हैं। ये कच्छ में मिलने वाले घास और पेड़ों के पत्ते आदि खाकर अपना गुजारा करते हैं। यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि ये जंगली गधें 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। पहली बार 1940 में जब इन गधों की गिनती कराई गई, तब ये देश भर में साढ़े तीन हजार से ज्यादा की संख्या में थे। परंतु 20 साल के अंदर ही उनकी संख्या घटकर केवल साढ़े तीन सौ रह गई। इसके बाद इन्हें बचाने के लिए सैंक्चुरी बनाने का फैसला किया गया। फिर 1972 में यह बनकर तैयार हुई। आज इन घुड़खर की संख्या अच्छी-खासी है।

पाजामा पहनते हैं यहां के गधे

फ्रांस के सेंट मार्टिन हार्बर पर गधों को पाजामा पहनाने का अनोखा प्रचलन है। यहां हर साल बहुत से देशी-विदेशी सैलानी आते हैं। सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं गधे, जो रंग-बिरंगे सूती कपड़े के पाजामे पहने होते हैं। बच्चे इन गधों पर ठीक वैसे ही सवारी करते हैं, जैसे घोड़ों पर की जाती है। दरअसल इन गधों को पाजामा पहनाने की प्रथा इसलिए शुरू की गई, क्योंकि यहां की नमकीन दलदली जमीन पर मक्खी और मच्छर ज्यादा हैं। गधों को उनके काटने से बचाने के लिए उन्हें पाजामा पहनाया जाता है।

चीनू और पोपू की शरारत

चीनू और पोपू चौथी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन थे अव्वल दर्जे के शरारती। ये दोनों कहीं पर भी कोई शरारत का मौका नहीं छोड़ते थे। अगर कोई उन्हें कहीं जाने का सीधा रास्ता पूछता तो वे उसे उल्टा रास्ता बता देते। अगर कोई फल वाला गुजरता तो वे उसे बातों में लगाकर उसके फल गायब कर देते। अपनी क्लास में भी वे खूब शरारत करते थे।

एक दिन रिक्कू क्लास में यूनीफॉर्म की काले रंग की नई पेंट पहनकर आया और चीनू को शरारत सूझी। वह पोपू से बोला- 'आज रिक्कू की पैंट ढीली करते हैं। आज यह नई पेंट पहनकर बहुत स्मार्ट समझ रहा है अपने आपको।' पोपू बोला- 'तो क्या करना है?' चीनू ने कहा- 'देखते जाओ मैं क्या करता हूं।' रिक्कू इंटरवल के समय अपनी सीट से उठकर कहीं बाहर गया हुआ था कि मौका देखते ही चीनू ने एक चॉक से उसकी सीट पर 'शरारती रिक्कू' लिख दिया। यह कुछ इस तरह उल्टे अक्षरों में लिखा कि छपकर सीधा लगे। इंटरवल खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गये। रिक्कू भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया।

क्लास टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवाने के लिए रिक्कू को बुलाया। रिक्कू बड़े आराम से मुस्कराहट के साथ जब ब्लैक बोर्ड पर टीचर की बताई हुई बात लिखने लगा तो उसकी पैंट के पीछे 'शरारती रिक्कू' छपा देखकर सब बच्चे हंसने लगे। टीचर ने हंसने का कारण पूछा तो सभी ने रिक्कू की पेंट की तरफ इशारा किया। क्लास टीचर ने उसकी पेंट पर छपे शब्दों को पढ़ा तो बड़ी हैरान हुईं। पूछा कि ये किसकी शरारत है, तो सभी चुप थे।

रिक्कू बेचारा यह लिखा देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। क्लास टीचर का ध्यान जब चीनू और पोपू की तरफ गया तो वे दोनों नीचे निगाहें किए हुए थे। क्लास टीचर समझ गई थीं कि यह इन्हीं दोनों की शरारत होगी। बाद में उन दोनों ने मान लिया कि यह उन्हीं की शरारत है। क्लास टीचर ने उन्हें वार्निंग (चेतावनी) देकर छोड़ दिया था।

कुछ दिन बाद चीनू और पोपू को फिर शरारत सूझी। रिक्कू का दोस्त मीकू रोजाना अच्छी-अच्छी स्वादिष्ट चीजें घर से अपने टिफिन में लेकर आता था। मीकू रिक्कू के साथ ही अपना खाना शेयर करता था और चीनू-पोपू को दिखा-दिखाकर खाना खाता था। पोपू ने चीनू से कहा कि अबकी बार मीकू को मजा चखाया जाए और यह मजा मैं चखाऊंगा। ये बड़ा हमें अपना खाना दिखा-दिखा कर खाता है और चिढ़ाता है। दोनों ने योजना बनाई कि इसके टिफिन में कुछ ऐसा रखा जाए कि इसे नानी याद आ जाए। दोनों आपस में विचार कर ही रहे थे कि क्या रखा जाए कि तभी पोपू के दिमाग में एक आइडिया आ गया।

उसने चीनू से कहा कि कल स्पोर्ट्स पीरियड में मीकू के टिफिन को खाली करके उसमें हरी-हरी घास भरनी है। दूसरे दिन अपनी योजना के अनुसार पोपू कुछ घास और दो-चार हरी मिर्चें ले आया।

इंटरवल से पहले स्पोर्ट्स पीरियड था तो सभी बच्चे प्लेग्राउंड में जाने लगे। मीकू भी रिक्कू के साथ चला गया। तभी पोपू और चीनू दोनों ने मिलकर उसका टिफिन खाली करके उसमें हरी मिर्च और घास भर दी और उसके टिफिन में जो भी चीजें थीं, सब जल्दी से खा-पीकर बराबर कर दीं। इसके बाद वे दोनों प्लेग्राउंड में चले गये। जब इंटरवल समाप्त हुआ तो सभी बच्चे क्लास में आकर अपने-अपने टिफिन खोलकर लंच करने लगे। चीनू और पोपू भी अपना लंच कर रहे थे। मीकू ने अपना टिफिन खोला तो उसे देखकर भौचक्का रह गया। सभी बच्चे उसके टिफिन में घास देखकर हंसने लगे और कमेंट करने लगे कि आज तो जानवरों का खाना लेकर आए हो।

इधर चीनू और पोपू बड़े मजे से कुछ इस तरह से लंच कर रहे थे, जैसे वे मीनू और रिक्कू को चिढ़ा रहे हों। उन्होंने कुछ सहानुभूति दिखाते हुए और आश्चर्य करके मीकू से कहा कि यह जरूर किसी की शरारत है। आओ आज हमारे साथ लंच कर लो। मीकू मन ही मन सोच रहा था कि यह किसकी शरारत हो सकती है, तभी रिक्कू ने इशारा किया कि यह इन दोनों का ही काम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ भी शरारत की थी।

जब क्लास टीचर क्लास में आईं तो बच्चों ने उन्हें मीकू के टिफिन में घास वाली बात बताई। टीचर पहले तो थोड़ा मुस्कराईं, फिर गुस्से में बोलीं- 'ये किसका काम है?' चीनू और पोपू क्लास टीचर के सामने तो बहुत सीधे बन जाते थे, लेकिन टीचर के जाते ही शरारतें शुरू कर देते थे। अभी दोनों एकदम शांत थे। टीचर की निगाह जब इन दोनों पर गई तो पहले तो उन्होंने कहा कि हमने यह काम नहीं किया, लेकिन जब टीचर ने सही बात बताने पर दबाव डाला तो उन्होंने अपनी गलती मान ली।

टीचर चीनू और पोपू को अपने कमरे में ले गईं और उनसे प्यार से पूछा कि वे ऐसी शरारतें क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया- 'जो हमें किसी बात पर चिढ़ाता है तो बहुत बुरा लगता है। हम उससे बदला ले लेते हैं। मीकू जब रिक्कू के साथ लंच करता था तो अपना खाना शेयर कराने की बजाए हमें दिखा-दिखाकर खाता था और चिढ़ाता था। और रिक्कू जब भी कोई नई शर्ट या पेंट पहनता तो हमें चिढ़ाता और अपने को ऐसा शो करता जैसे कि वो क्लास का हीरो हो। हमें ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने ऐसा किया।'

क्लास टीचर ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि अब वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करें, जिससे किसी बच्चे को कोई परेशानी हो और क्लास में भी सब बच्चों को समझाया कि सभी बच्चे आपस में मिल-जुलकर रहें। कोई किसी को किसी बात पर न चिढ़ाए।

अगले दिन मीकू और रिक्कू इंटरवल में लंच करने लगे तो उन्होंने चीनू और पोपू को भी लंच शेयर करने के लिए बुला लिया। अब चारों साथ-साथ ही लंच करते थे और बड़े अच्छे दोस्त बन गये थे। चीनू और पोपू की शरारतें भी अब कुछ कम होने लगी थीं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर फिर झड़प, बढ़ा तनाव; तालिबान के कई सदस्यों को मारने का दावा

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे गुलिस्तान सेक्टर में अफगान तालिबान के कथित हमले को नाकाम करने का दावा किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने इस कार्रवाई में तालिबान के कई सदस्यों को मार गिराया। यह घटना दोनों पड़ोसी देशों के बीच करीब तीन महीने तक अपेक्षाकृत शांति रहने के बाद फिर बढ़े तनाव के बीच हुई है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक पुलिस प्रतिष्ठान पर हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने गुरुवार को अफगानिस्तान में 10 ठिकानों पर हमला किया था। इस्लामाबाद का कहना था कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ड्रोन लॉन्च करने और उन्हें रखने के लिए किया जा रहा था। दोनों देशों के बीच फरवरी में भी संघर्ष हुआ था। इसके बाद तनाव जारी रहने के दौरान मार्च में काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। अफगान तालिबान ने कहा था कि मार्च में किया गया हवाई हमला एक मादक पदार्थ पुनर्वास केंद्र को निशाना बनाकर किया गया था।

बांग्लादेश 2024 में फासीवाद से मुक्त हुआ: संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री तारीक रहमान

न्यूयार्क, एजेंसी। बांग्लादेश 2024 में फासीवाद से मुक्त हुआ और सरकार देश को 'ठीक' करने के लिए सुधार, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण की रणनीति पर काम कर रही है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह बात कही। रहमान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण बांग्ला में दिया। वह अपने परिवार के तीसरे सदस्य हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। उनसे पहले उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के साथ मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर चुकी हैं। उनके पिता जियाउर रहमान ने 1980 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, जबकि उनकी मां ने 1993 में विश्व नेताओं को संबोधित किया था। रहमान ने गुरुवार को अपने पहले संबोधन में कहा, 'डेढ़ दशक से अधिक समय के फासीवादी शासन और शोषण को खत्म करने के बाद बांग्लादेश 2024 में फासीवाद से मुक्त हुआ।

नेपाल-चीन सीमा पर बाढ़ के एक महीने बाद भी 50 से ज्यादा यूक्रेनी लापता, परिवारों को जवाब का इंतजार

काठमांडू, एजेंसी। ओलेना कलिनिचेंको चीन से खरीदी गई गुलदाउदी की चाय अपने साथी के साथ साझा करने का इंतजार कर रही थीं। उनके साथी ओलेस विसिच ने कहा, 'उन्होंने कहा था, जब मैं घर लौटूंगी तो हम चीनी फूलों से बनी चाय साथ में पिएंगे।' अब वह एक महीने से ओलेना की खबर का इंतजार कर रहे हैं। ओलेना और हजारों अन्य लोग नेपाल-चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के दौरान लापता हो गए थे। ओलेना की आखिरी ज्ञात लोकेशन स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर एक सीमा चौकी से चीन से बाहर निकलते समय दर्ज हुई थी। इसके 15 मिनट बाद बाढ़ आ गई थी। 36 वर्षीय कलिनिचेंको उन 56 लोगों के समूह का हिस्सा थीं, जिनमें ज्यादातर यूक्रेनी नागरिक थे। यह समूह आध्यात्मिक प्रवास के लिए तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत गया था। इन परिवारों की स्थिति बताती है कि आपदा में लापता लोगों को बचाने, उनके शव बरामद करने और उनकी पहचान करने की प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली हो सकती है।

पोलैंड की कैथोलिक मोनेस्ट्री में चाकू से हमला, पादरी की दर्दनाक मौत, 4 लोग गंभीर घायल

जारोस्लाव , एजेंसी। दक्षिण पूर्वी पोलैंड के जारोस्लाव शहर स्थित ऐतिहासिक बेनेडिक्टिन सिस्टर्स मठ में चाकूबाजी की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गुरुवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान एक 31 वर्षीय सनकी युवक ने पादरियों और श्रद्धालुओं पर बड़े चाकू से अचानक ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हुए पादरियों में से एक की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि तीन पुरुषों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय पुलिस ने आरोपी नागरिक को हिरासत में ले लिया है तथा जारोस्लाव शहर में आपातकालीन क्राइसिस मैनेजमेंट प्रक्रिया लागू कर दी गई है।

व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग के लिए ट्रम्प का भव्य स्टेट डिनर: मेलानिया ने तैयार किया खास मेन्यू

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार रात व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के सम्मान में एक भव्य 'स्टेट डिनर' (राजकीय भोज) की मेज़बानी की। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गर्मजोशी के बीच आयोजित इस डिनर में न केवल राजनीतिक बल्कि वैश्विक व्यापार और टेक जगत के सबसे बड़े चेहरे एक छत के नीचे नज़र आए। मेलानिया ट्रम्प ने तैयार किया मेन्यू: अमेरिकी और चीनी स्वाद का संगमस्टेट डिनर का विशेष मेन्यू अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प की देखरेख में तैयार किया गया।

सूपः डिनर की शुरुआत पीले स्क्वैश से बने गाढ़े सूप से हुई, जिसमें जंगली मशरूम, ताज़ी जड़ी-बूटियां, कुरकुरा पैनसेटा और हरे प्याज का तेल शामिल था। मुख्य व्यंजनः तिल की परत वाली खास 'सी-बास' मछली परोसी गई। इसके साथ चीन में बेहद लोकप्रिय हरी सब्जी 'बोक चॉय', भुना हुआ बैंगन और विशेष हरी चटनी दी गई।

मिठाई (डेज़र्ट): मीठे में वनीला फ्लेवर की नरम क्रीम, खट्टी चेरी और अखरोट से बनी मिठाई के साथ आइसक्रीम पेश की गई। इस आइसक्रीम में व्हाइट हाउस के बगीचों में तैयार किया गया प्राकृतिक शहद इस्तेमाल हुआ।

टेक दिग्गजों का महाजुटान : डिनर में अमेरिका के प्रमुख उद्योगपतियों और सिलिकॉन वैली के शीर्ष टेक

दिग्गजों ने शिरकत कीः शामिल प्रमुख हस्तियांः टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क, अमेज़न के जेफ बेजोस, गूगल (अल्फाबेट) के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन-एआई के सैम ऑल्टमैन व ग्रेग ब्रॉकमैन, एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग तथा डेल टेक्नोलॉजीज के माइकल डेल मौजूद रहे। चर्चा के केंद्रः ओपन-एआई के सैम ऑल्टमैन आयोजन स्थल के बाहर प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देते दिखे, जबकि एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग अपने चिर-परिचित काले लेदर जैकेट के स्थान पर ब्लैक टक्सीडो पहनकर पहुंचे।

अमेरिका-चीन रिश्ते पहले से बेहतर': तोहफे में दिया बाल्ड ईगल

डिनर के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने दोनों देशों के संबंधों की तारीफ करते हुए कहाः मजबूत जन-संबंधः 'भले ही हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं भिन्न हों, लेकिन दोनों देशों के नागरिकों के बीच रिश्ते बेहद प्रगाढ़ हैं। आज दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं।' उन्होंने अपने बीजिंग दौरे के भव्य स्वागत को याद करते हुए जिनपिंग को वैसा ही सम्मान देने की बात कही। विशेष उपहारः ट्रम्प ने शी जिनपिंग को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी 'बाल्ड ईगल' (Bald Eagle) की लगभग 3 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा उपहार में दी और कहा कि यह अमेरिका की आजाद व ऊंची उड़ान भरने वाली चेतना का प्रतीक है।

डिनर से पहले 2 घंटे चली द्विपक्षीय वार्ता : स्टेट डिनर से ठीक पहले व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक गहन द्विपक्षीय बातचीत हुई, जो निर्धारित समय से एक घंटा अधिक चली। बंद कमरे में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , व्यापार संतुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया की एंट्री को लेकर हुए इस विवाद का असर ट्रम्प-जिनपिंग की मुलाकात की टीवी कवरेज पर भी पड़ा। अमेरिका के कई बड़े टीवी नेटवर्क ने दोनों नेताओं की शुरुआती मुलाकात का लाइव प्रसारण नहीं किया। इसी दौरान ओवल ऑफिस में ट्रम्प ने चीनी पत्रकारों को लेकर मजाक करते हुए कहा कि चीन की मीडिया सबसे दोस्ताना है। डिनर के दौरान ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और चीन की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से बेहतर हैं। ट्रम्प ने अपने बीजिंग दौरे को याद करते हुए कहा कि चीन में उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ था, अब अमेरिका भी जिनपिंग को वैसा ही सम्मान देना चाहता है। इस दौरान ट्रम्प ने जिनपिंग को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल का करीब 3 फीट ऊंचा स्टैच्यू भी तोहफे में दिया।

बलूचिस्तान: बलूच लड़ाकों ने 25 हमलों में मारे 18 पाकिस्तानी सैनिक

क्वेटा, एजेंसी। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने गुरुवार को पिछले कुछ दिनों में पूरे बलूचिस्तान में 25 ऑपरेशनों की जिम्मेदारी ली है। स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी बलों को निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 18 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए।

द बलूचिस्तान पोस्ट को जारी एक बयान में बीएलए के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने कहा कि उसके लड़ाकों ने 14 से 23 सितंबर के बीच प्रांत के कई हिस्सों में हमले किए, जिनमें पंजगुर, केच, खारान, खुजदार, मस्तुंग, वाशुक, नुश्की और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभियानों के दौरान बीएलए ने पाकिस्तानी सैन्य काफिलों और चौकियों, निगरानी ढांचे, आपूर्ति मार्गों और जिसे समूह ने 'डेथ स्क्वॉड' बताया, उस पर हमला किया। बयान के अनुसार, बीएलए ने 22 सितंबर को क्वेटा के पास दश्त के टेरा माइल इलाके में पैदल गश्त के दौरान सेना के बम निरोधक दस्ते के सदस्यों को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से निशाना बनाया। समूह ने दावा किया कि हमले में एक पाकिस्तानी जवान की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। बीएलए ने कहा कि उसी दिन लड़ाकों ने खुजदार में बागबाना पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया और वहां रखे हथियारों और उपकरणों को जब्त कर लिया। समूह ने कहा कि बाद में पुलिस एंटी-टेररिस्ट फोर्स (एटीएफ) के कर्मी, 'डेथ स्क्वॉड' के सदस्यों के साथ इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर हमला किया गया। उसने कहा कि कथित सशस्त्र समूह के कई सदस्य मारे गए और थानाध्यक्ष (एसएचओ) मुनीर आलम जट्टक सहित पुलिस कर्मी घायल हो गए। बीएलए के अनुसार, उसके लड़ाकों ने 20 सितंबर को नुश्की में बाईपास रोड पर शहीद बालाच खान स्टेडियम के पास पाकिस्तानी सैन्य बलों को भी निशाना बनाया, जिसमें दो जवान मारे गए और चार अन्य घायल हो गए। उसने आगे दावा किया कि बुलेदा के कोश्क इलाके में एक सैन्य चौकी पर ग्रेनेड-लॉन्चर से कई राउंड फायरिंग की गई। समूह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने 21 सितंबर को मांड में रादिग पर कब्जा कर लिया, प्रमुख स्थानों पर नाकाबंदी की और भारी और स्वचालित हथियारों का उपयोग करके पाकिस्तानी सेना के मुख्य शिविर पर हमला किया। इससे पहले, 18 सितंबर को, उसने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने मांड में बलोचाबाद और बुल्लो पर कब्जा कर लिया, प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया, और ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। बीएलए ने आरोप लगाया कि बाद में पाकिस्तानी बलों ने नागरिक बस्तियों को निशाना बनाने के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया।

यूएन में बालेंद्र शाह का पहला भाषण: आपदा प्रबंधन पर दिया जोर

न्यूयॉर्क , एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नेपाल, भारत और चीन के नेतृत्व में एक साझा तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की अपील की। बालेंद्र शाह ने कहा कि इस तंत्र के जरिए तीनों देश उपग्रह से मिले आंकड़े और विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं। साथ ही खतरनाक ग्लेशियल झीलों की निगरानी और संयुक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब कोई आपदा आए तो सीमाओं के पार राहत और सहायता के लिए समन्वय किया जाना चाहिए।

बालेंद्र शाह ने भारत-चीन से की क्या अपील : नेपाल के पीएम शाह ने कहा, 'हम नेपाल, भारत और चीन के नेतृत्व में हिमालयी जलवायु के लिए तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस तंत्र के जरिए उपग्रह डेटा और विशेषज्ञता साझा करें। खतरनाक ग्लेशियल झीलों की निगरानी करें। संयुक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करें। जब आपदा आए तो सीमाओं के पार सहायता का समन्वय करें। हिमालय खंडित सूचनाओं की सीमा के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रयोगशाला बने। नेपाल बाढ़ त्रासदी को लेकर क्या बोले बालेंद्र शाह? नेपाल के प्रधानमंत्री ने बाढ़ के बाद मदद के लिए विभिन्न देशों और संगठनों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, 'मैं बाढ़ के बाद हमारी सहायता के लिए आगे आने वाले सभी लोगों के प्रति नेपाल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे तत्काल पड़ोसी भारत और चीन ने तेजी से और उदार सहायता प्रदान की। अन्य मित्र देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, मानवीय सहायता एजेंसियों, परोपकारी संगठनों और दुनिया भर के लोगों ने नेपाल का साथ दिया। उन सभी से मैं नेपाल की कृतज्ञ जनता की ओर से धन्यवाद कहता हूं।

उत्तर कोरिया ने किया उन्नत 240 मिमी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण, क्षेत्र में बढ़ा तनाव

प्योंगयांग, एजेंसी। उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य तोपखाने क्षमताओं को आधुनिक बनाते हुए 240 मिमी क्षमता वाले उन्नत मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है। गुरुवार को केसीएनए और योनहाप न्यूज एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षण 22 सितंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

नए रॉकेटों में ऑटोनॉमस पिनपॉइंट गाइड सिस्टम जोड़ा गया है, जिससे इनकी अधिकतम मारक क्षमता 115 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इस परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपनी दक्षिणी सीमा पर सबसे घातक और विनाशकारी हमलावर बल तैनात करने पर जोर दिया है।

240 मिमी रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण, 115 किलोमीटर तक रेंज : उत्तर कोरिया ने 240 मिमी क्षमता वाले

मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से उन्नत रॉकेटों का परीक्षण किया। योनहाप न्यूज एजेंसी ने सरकारी मीडिया केसीएनए के हवाले से बताया कि यह परीक्षण 22 सितंबर को किया गया था। उत्तर कोरिया के अनुसार नए रॉकेटों में ऑटोनॉमस पिनपॉइंट गाइड सिस्टम लगाया गया है, जिससे उनकी सटीकता बढ़ाने का दावा किया गया है। सामान्य बैलिस्टिक उड़ान मोड में इनकी मारक क्षमता करीब 100 किलोमीटर बताई गई है, जबकि ग्लाइड फ्लाइट वाले संयुक्त मोड में यह दूरी 115 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। प्योंगयांग ने दावा किया कि परीक्षण के दौरान रॉकेटों की सटीकता और प्रदर्शन की पुष्टि हुई है। यह परीक्षण देश की आर्टिलरी और मिसाइल प्रणालियों के आधुनिकीकरण की योजना का हिस्सा बताया जा रहा है।

दक्षिणी सीमा पर सैन्य क्षमता बढ़ाने का दावा : उत्तर कोरिया के सैन्य नेतृत्व ने इस परीक्षण के बाद दक्षिणी सीमा पर अपनी मारक क्षमता को और मजबूत करने की बात कही है। वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष पाक जोंग-चोन ने दक्षिणी सीमा पर आधुनिक और लंबी दूरी की सैन्य प्रणालियों को केंद्रित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया चाहता है पिछले कुछ वर्षों में प्योंगयांग ने दक्षिण कोरिया की सीमा के नजदीक इस्तेमाल की जा सकने वाली कई आर्टिलरी और मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड किया है। उत्तर कोरिया ने 2023 में दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को 'शत्रुतापूर्ण दो राज्य' के रूप में परिभाषित किया था।

यूएन में शहबाज शरीफ से हाफिज सईद पर सवाल, मुंह छिपाते नजर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

इस्लामाबाद , एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हाफिज सईद के मुद्दे पर सीधे सवालों का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश करते समय पत्रकार ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेगा। शहबाज शरीफ ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। बाद में जब वह यूएन मुख्यालय से बाहर निकले तो उनसे फिर पूछा गया कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद पर मुकदमा कब चलाया जाएगा। इस सवाल पर भी वो मुंह छिपाते हुए चलते चले गए। हाफिज सईद पर शहबाज शरीफ से क्या-क्या पूछा गया?

शहबाज शरीफ से दोनों सवाल सीधे तौर पर पाकिस्तान में आतंकवाद और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े थे। सवाल था, 'प्रधानमंत्री, आप आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेंगे?' लेकिन शहबाज ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद यूएन मुख्यालय से निकलते समय उनसे पूछा गया, 'लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद पर मुकदमा कब चलाएंगे?' इस बार भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। इस पूरे घटनाक्रम ने यूएन में पाकिस्तान के आतंकवाद संबंधी रिकॉर्ड और हाफिज सईद पर कार्रवाई के सवाल को फिर चर्चा में ला दिया। हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और प्रमुख रहा है। भारत ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में भी उसका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके अलावा अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। एनआईए ने जुलाई 2026 में दाखिल पूरक आरोपपत्र में उस पर व्यक्तिगत रूप से और लश्कर-ए-तैयबा तथा उसके सक्रिय सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख के तौर पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक को निशाना बनाया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए की जांच के बाद दाखिल पूरक आरोपपत्र में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को भी आरोपी बनाया गया। जांच एजेंसी ने उस पर हमले की व्यापक साजिश में भूमिका होने का आरोप लगाया है।

नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर खोले पत्ते: रिश्तों को बताया बेहतरीन, जयशंकर से मुलाकात का भी किया जिक्र

वॉशिंगटन , एजेंसी। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आता रहा है, लेकिन अभी नेपाल और भारत के बीच रिश्ते अच्छे दौर में हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडो भारत के साथ संबंधों में मतभेदों के बजाय अवसरों पर ध्यान देते हुए व्यावहारिक तरीका अपना रहा है।

भारत के साथ रिश्तों पर नेपाल के विदेश मंत्री ने क्या कहा : शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल और भारत के संबंध बहुत मजबूत और कई स्तरों वाले हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल के कुल व्यापार का करीब दो-तिहाई हिस्सा भारत के साथ होता है। दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी काफी मजबूत हैं। खनाल ने कहा कि राजनीतिक स्तर पर कभी-कभी रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन मौजूदा समय में दोनों देशों के संबंधों को वह बेहतरीन मानते हैं। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल की नई सरकार के बीच संबंधों से जुड़े सवाल के जवाब में कही।

जयशंकर से मुलाकात में किन मुद्दों पर हुई बात : खनाल ने बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच भारत-नेपाल संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें विकास साझेदारी और ऊर्जा सहयोग की प्रगति पर चर्चा हुई। नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। यह बातचीत संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर हुई। भारत और चीन के बीच संतुलन को लेकर पूछे गए सवाल पर खनाल ने कहा कि नेपाल अब रिश्तों को केवल वैचारिक नजरिए से देखने के बजाय व्यावहारिक सहयोग पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा जैसे विवादित मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन नेपाल का मौजूदा तरीका यह देखने का है कि सहयोग के कौन-कौन से अवसर मौजूद हैं।

भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को उन्होंने इसी व्यावहारिक नीति का उदाहरण बताया। खनाल ने कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था आयात पर काफी निर्भर है, इसलिए ऊर्जा और व्यापार में सहयोग उसके लिए महत्वपूर्ण है। खनाल ने कहा कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसके लिए बड़ी आर्थिक संभावना बन सकती है। उन्होंने भारत के साथ 1,700 किलोमीटर से अधिक लंबी खुली सीमा का जिक्र किया। यह सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जुड़ती है। उन्होंने बताया कि नेपाल के पास आर्थिक रूप से उपयोगी करीब 43 गीगावाट जलविद्युत क्षमता है और देश 2035 तक 28,000 मेगावाट तक पहुंचने की दिशा में काम करना चाहता है। इससे भारत और आगे बांग्लादेश को स्वच्छ बिजली निर्यात करने की संभावना है।

यूएन में 75 देशों ने नेतन्याहू का बायकॉट किया: हूटिंग हुई तो 3 मिनट चुप खड़े रहे, फिर बोले- कायर बाहर चले जाएं

न्यूयॉर्क, एजेंसी। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। जैसे ही वो मंच पर आए तो 75 देशों के प्रतिनिधियों ने हूटिंग करके उनका विरोध किया, फिर बाहर चले गए। इस घटनाक्रम के बाद नेतन्याहू करीब 3 मिनट तक चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, भाषण शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर यहां कोई और कायर है तो बाहर चला जाए। हालांकि, इस दौरान गैलरी नेतन्याहू के समर्थकों से भरी हुई थी। उन्होंने तालियां बजाकर नेतन्याहू का स्वागत किया और 'अम यिसराइल चाई' यानि 'इजराइल की जनता जिंदा है' के नारे लगाए। नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा, ईरान, लेबनान पर इजराइली कार्रवाई का जिक्र किया। ट्रम्प की तारीफ, न्यूयॉर्क मेयर ममदानी और यूरोप के नेताओं की आलोचना की।

गाजा- इजराइली सेना के हमले का बचाव : नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले का जिक्र करते हुए इजराइल की सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों ने जिस तरह इजराइलियों को मारा, वह बेहद भयावह था। ऐसी भयावहता की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

नेतन्याहू ने आगे कहा, दुश्मनों को लगा था कि इजराइल टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हम उठे और शेरों की तरह लड़े। नेतन्याहू ने गाजा में इजराइल पर नरसंहार करने के आरोप को खारिज किया। उन्होंने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ बताया। नेतन्याहू ने कहा, 'इजराइल ने नरसंहार नहीं किया। इजराइल ने नरसंहार को रोका। अगर हमास के समर्थकों को मौका मिलता तो वे हर यहूदी को मार देते। '

लेबनान- हिजबुल्लाह को पेजर अटैक की याद दिलाई : नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई उस कार्रवाई का भी जिक्र किया, जिसमें संगठन के सदस्यों के पास मौजूद पेजर में धमाके हुए थे। उन्होंने कहा, क्या आपको पेजर याद हैं? हिजबुल्लाह को तो जरूर याद होंगे। 17 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया में हजारों पेजर एक साथ फटे थे, जिससे 3,000 से अधिक लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हो गई थी। ईरान- डेलीगेशन को स्टारलिंक गिफ्ट करने बात कही नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइलों के खतरे का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में मौजूद लोगों से सवाल किया कि अगर एक टन की ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इस इमारत पर गिर जाए तो क्या होगा। इससे पूरा इलाका तबाह हो सकता है। उन्होंने ईरान के नेताओं को 'तेहरान का तानाशाह' बताया और कहा कि वे अपने ही लोगों से डरते हैं। उन्होंने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का एक डिवाइस दिखाया और कहा कि इससे ईरान के लोग खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि वे यह डिवाइस ईरानी डेलीगेशन के लिए छोड़कर जाएंगे। अगर वे अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएं या उसका साथ छोड़ दें, तो स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट चला सकेंगे और सोशल मीडिया पर अपनी बात दुनिया को बता सकेंगे। नेतन्याहू के हॉल से जाने के बाद जब ईरानी अधिकारी वहां पहुंचे, तो एक इजराइली अधिकारी उनके पास गया। उसने ईरानी अधिकारियों से स्टारलिंक डिवाइस लेने की अपील की और कहा कि यह उनके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू के हॉल से जाने के बाद जब ईरानी अधिकारी वहां पहुंचे, तो एक इजराइली अधिकारी उनके पास गया।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पालमपुर :महिला को 7 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट 15 लाख ठगे

पालमपुर (एजेंसी)। उपमंडल की एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई है, जहां शातिरों ने उसे सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 15 लाख रुपये ऐंठ लिए। ठगों ने महिला को उसके बैंक खातों के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का डर दिखाकर यह बड़ी रकम हड़पी। पीड़िता की शिकायत पर साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता को 18 सितंबर को दो अलग-अलग नंबरों से फोन आए। कॉल करने वालों ने खुद को दिल्ली के दरियागंज पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया। उन्होंने महिला पर यह कहकर दबाव बनाया कि उसके बैंक खातों का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। जांच के नाम पर, शातिरों ने महिला को लगातार अपनी निगरानी में रखा और उसे किसी भी परिजन या परिचित से संपर्क न करने की कड़ी हिदायत दी। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के गंभीर डर से, महिला ने शातिरों द्वारा उपलब्ध कराए गए एक बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड पर नेफ्ट के माध्यम से 15 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम ट्रांसफर होने के बाद जब महिला को अपनी ठगी का अहसास हुआ, तो उसने तुरंत साइबर थाना धर्मशाला पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है।

बिहार में चलती तीर्थयात्री बस में भीषण आग, बाल-बाल बचे 60 यात्री

खगड़िया (एजेंसी)। बिहार के खगड़िया जिले में अहले सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब मानसी थाना क्षेत्र में एनएच-31 पर नेपाल से गया जा रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार करीब 60 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना अनिल होटल के सामने एनएच-31 पर हुई। बस में सवार सभी यात्री गया में पिंडदान करने जा रहे थे। यात्रियों ने बताया कि पहले बस के एक टायर से धुआं निकलता दिखाई दिया, जो तेजी से बस के अंदर फैलने लगा। खतरे को भांपते हुए यात्रियों ने तुरंत बस से नीचे उतरना शुरू कर दिया। सभी के उतरने के कुछ ही देर बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। यात्रियों की त्वरित प्रतिक्रिया और सूझबूझ के कारण सभी लोग सुरक्षित बच गए। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण टायर से निकला धुआं बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई है।

130 की गति से दौड़ रही दुरंतों एक्सप्रेस पर पथराव, 3 कोच के शीशे टूटे

वाराणसी (एजेंसी)। नागपुर(ईएमएस)। देश की प्रमुख ट्रेनों में शुमार दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नागपुर से मुंबई जा रही यह ट्रेन शुक्रवार की रात को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी अचानक उस पर पत्थरों से हमला किया गया। इस घटना से ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए और तीन कोच के शीशे टूट गए। इससे पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में प्रीमियम ट्रेनों, जिनमें वंदे भारत सेमी हाई-स्पीड ट्रेन भी शामिल है, पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके कि रेलवे इन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। घटना शुक्रवार रात लगभग 8:27 बजे नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12290) के बोरखेड़ी और सिंदी के बीच सफर के दौरान हुई। अज्ञात व्यक्तियों ने चलती ट्रेन को निशाना बनाकर पत्थर फेंके, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन के ए-1, बी-2 और बी-5 कोच की खिड़कियों के कांच चटक गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में एक यात्री को मामूली चोट भी आई है। पथराव की सूचना मिलते ही ट्रेन को वर्धा स्टेशन पर करीब आधे घंटे के लिए रोका गया, जहां रेलवे और संबंधित अधिकारियों ने गहन जांच पड़ताल की।

डीएमके पर विजय का हमला : आलोचनाएं बेअसर, सवाल जारी रखूंगा

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख सी.जोसेफ विजय ने कहा है कि विपक्ष, खासकर द्रमुक की आलोचनाएं उन पर बेअसर हैं और वे द्रमुक के पुराने रिकॉर्ड पर लगातार सवाल उठता रहूंगा। यह बात उन्होंने मदुरांतकम विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार मरगतम कुमारवेल के प्रचार के दौरान कही। विजय ने द्रमुक की रणनीति पर निशाना साधा, जिसमें उनकी आलोचनाओं को पुराना बताकर खारिज किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि द्रमुक मानती है कि युवा पीढ़ी 50 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामलों से अनजान है, जिससे वह अपनी बेदाग छवि बनाए रखने में सफल रही है। विजय ने कहा, जब वे पुराने मामले उठाते हैं,तब द्रमुक घटिया और मानहानिकारक हमले करती है। अपनी 'मोटी चमड़ी' का जिक्र कर विजय ने कहा कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने 30-35 साल तक बहुत कुछ देखा है, इसलिए ये हमले उनके लिए नए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे इससे भी ज़्यादा की उम्मीद करते हैं।

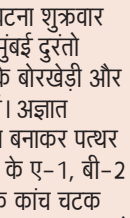

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चार्जशीट में सीसीटीवी से लेकर बैंक खातों तक का ब्योरा; 700 खाते खंगाले

85 बार रकम ले जाते दिखा अविनाश, चैट में कैश के बंडलों का जिक्र

अयोध्या, एजेंसी।

राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई रकम की कथित चोरी की जांच में पुलिस की चार्जशीट ने मामले की परतें और खोल दी हैं। जांच के मुताबिक, गणना कक्ष में चढ़ावे की रकम से छेड़छाड़ का सिलसिला एक-दो बार नहीं, बल्कि कई मौकों पर हुआ। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में अविनाश शुक्ला उर्फ शनि 85 बार रकम चोरी करते दिखाई दिया। इतना ही नहीं, चार बार वह दूसरे आरोपियों को चोरी में सहयोग करते भी नजर आया।

चार्जशीट में पुलिस ने केवल कैमरों के फुटेज को आधार नहीं बनाया है। मोबाइल डाटा, टेक्स्ट चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और बैंक खातों के लेनदेन को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, करीब 700 बैंक खातों को खंगाला गया। इनमें ट्रस्टियों, कर्मचारियों, गणना कर्मियों, आरोपियों और संदिग्धों के खातों के साथ ट्रस्ट के बैंक खाते भी शामिल रहे। इसी जांच में पुलिस ने दर्ज किया कि चंपत राय के नाम कोई निजी बैंक खाता नहीं मिला।

फुटेज में दर्ज गतिविधियां

चार्जशीट का सबसे बड़ा हिस्सा सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा है। पुलिस ने अलग-अलग तारीखों और घटनाओं के फुटेज का विश्लेषण कर आरोपियों की गतिविधियों का ब्योरा तैयार किया है। पुलिस के मुताबिक, अविनाश शुक्ला उर्फ शनि 85 बार चढ़ावे की रकम हटाते या चोरी करते दिखाई दिया।

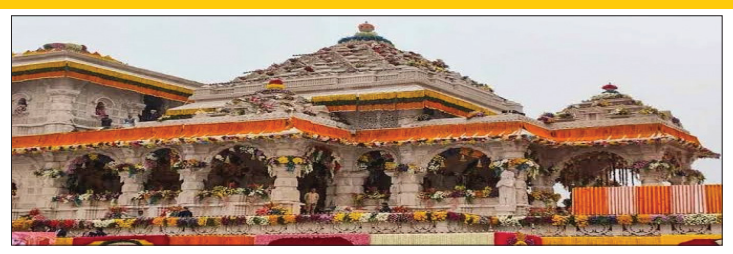

चार बार वह दूसरे आरोपियों को चोरी में सहयोग करता भी नजर आया। करुणेश पांडेय के बारे में चार्जशीट में कहा गया है कि वह दो बार रकम चोरी करते और 68 बार सह-अभियुक्तों की मदद करते दिखाई दिया। मनीष कुमार यादव पर 16 बार चढ़ावे की रकम अपने पास रखने और 19 बार दूसरे आरोपियों का सहयोग करने का आरोप है। लवकुश मिश्रा एक बार रकम चोरी करते और 52 बार अन्य आरोपियों की मदद करते दिखाई दिए। रमाशंकर मिश्र के बारे में एक बार रकम हटाकर अपने पास रखने का उल्लेख है। सबसे अधिक सहयोग करने वालों में अनुकल्प मिश्रा का नाम भी सामने आता है। पुलिस के अनुसार, वह 56 बार अन्य आरोपियों को चढ़ावे की रकम हटाने में सहयोग करते सीसीटीवी में दिखाई दिया।

जुलाई के आखिरी सप्ताह का फुटेज भी अहम चार्जशीट में 25 से 30 जुलाई 2026 के सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख है। पुलिस के अनुसार, इस दौरान सुभाष श्रीवास्तव की मौजूदगी में गणना कक्ष में चढ़ावे की रकम की गिनती चल रही थी। इसी दौरान अविनाश शुक्ला उर्फ शनि रकम हटाकर अपने पास रखते दिखाई दिया। जांच एजेंसी ने इस फुटेज को इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि यह रकम की गिनती की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर हुई गतिविधियों से जुड़ा है। यानी पुलिस ने चोरी के आरोप को केवल रकम के हिसाब-किताब में अंतर से नहीं, बल्कि कैमरे में रिकॉर्ड हुई गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की है।

मोबाइल चैट में 'कैश के बंडल' की बातचीत

जांच का दूसरा अहम सिरा मोबाइल फोन से मिला डिजिटल डाटा है। चार्जशीट के मुताबिक, अनुकल्प मिश्रा के मोबाइल से अविनाश शुक्ला और लवकुश मिश्रा के साथ चढ़ावे की रकम को लेकर टेक्स्ट संदेश मिले। पुलिस के अनुसार, इन चैट में कैश के बंडलों को रखने, छिपाने, अदला-बदली करने और इधर-उधर ले जाने से संबंधित बातचीत का उल्लेख है। जांच में इन संदेशों को सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के साथ जोड़कर देखा गया। इसके अलावा आरोपियों के बीच लगातार संपर्क को लेकर सीडीआर का विश्लेषण भी किया गया। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया है कि संबंधित अवधि में आरोपियों के बीच लगातार संपर्क था। सीसीटीवी, डिजिटल, मौखिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मिलाकर पुलिस ने आपसी समन्वय और आपराधिक षड्यंत्र के साक्ष्य मिलने की बात कही है।

700 खातों में रकम का रास्ता तलाशा

जांच का दायरा केवल गणना कक्ष तक नहीं रहा। पुलिस ने करीब 700 बैंक खातों के लेनदेन की पड़ताल की। मकसद यह पता लगाना था कि संदिग्ध रकम कहीं बैंकिंग चैनल के जरिए आरोपियों या उनसे जुड़े लोगों तक पहुंची या नहीं। ट्रस्टियों, कर्मचारियों, गणना कर्मियों और संदिग्धों के खातों की जांच के साथ ट्रस्ट के बैंक खातों को भी देखा गया। डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खातों के लेनदेन को भी अन्य आरोपियों और संदिग्धों के खातों से मिलाकर जांचे जाने का उल्लेख है। इसी प्रक्रिया में चार्जशीट में यह तथ्य दर्ज किया गया कि चंपत राय के नाम कोई निजी बैंक खाता नहीं मिला। हालांकि, किसी व्यक्ति के नाम निजी बैंक खाता नहीं मिलना अपने आप में किसी आपराधिक आरोप की पुष्टि या खंडन नहीं करता। इस तथ्य का महत्व मामले के अन्य साक्ष्यों और न्यायिक परीक्षण के संदर्भ में ही तय होगा।

अगर गठबंधन नहीं करना है तो न करें, हम क्या किसी से भीख मांग रहे हैं?

-इकरा हसन के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया पलटवार

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान शुरु हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं करना है तो न करें। हम अपने काम पर लगे हैं। सांसद मसूद ने कहा कि न करें गठबंधन, कौन कह रहा है? हम क्या किसी से भीख मांग रहे हैं? जिसको जो करना है, वह करे। जब बारात चढ़ती है, तो बहुत सारे ढोल बजाने वाले भी होते हैं, नाचने-गाने वाले भी होते हैं। इन नाचने-गाने वालों को नाचने-गाने दीजिए। हम अपने काम पर लगे हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सपा विधायक शिवपाल यादव के बयान पर मसूद ने कहा कि यह उनकी सोच हो सकती है, कांग्रेस अपने काम पर लगी है। शिवपाल जो बात कह रहे हैं, वह पार्टी के अंदर ही अप्रासंगिक हो गए हैं। वह अपने नेता से यह बात अगर वह कहेंगे, तब तो उसके ऊपर कोई मायने होंगे, इसके अलावा कोई मायने नहीं हैं। मसूद ने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बता दें इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलना है। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों से इंडिया गठबंधन आहत होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लाभ देने वाले बयान कांग्रेस की ओर से आते रहे हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव तय करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं, यह केवल दबाव बनाने के लिए हैं। कांग्रेस यूपी-बिहार में कितना पानी में है, यह जगजाहिर है।

मणिपुर और नागालैंड के बड़े हिस्सों को अशांत क्षेत्र घोषित किया

नई दिल्ली , एजेंसी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के दो राज्यों, मणिपुर और नागालैंड के कई क्षेत्रों को आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (एएफएसपीए) के तहत अगले छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। यह घोषणा 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी और अगले छह महीनों के लिए लागू रहेगी, जब तक कि इसे तय समय से पहले वापस नहीं लिया जाता।

अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर के पूरे क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया है, सिवाय पांच जिलों के तेरह पुलिस थाना क्षेत्रों के। इन अपवादों में राजधानी इंफाल के साथ-साथ लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, पटसोई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नांबोल और काकचिंग पुलिस थाना क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों को अफस्पा के दायरे से बाहर रखा गया है। नागालैंड के संदर्भ में, गृह मंत्रालय ने नौ पूर्ण जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलक, फेक, पेरेन और मेलुरी जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पांच अन्य जिलों के इक्कीस पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अफस्पा के दायरे में लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि यह घोषणा अफस्पा की धारा तीन के तहत की गई है। नागालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है। यह घोषणा मार्च 2026 में जारी पूर्व अधिसूचना का विस्तार है, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2026 से छह महीनों के लिए इन क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया था। जिन पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया है, वे इस प्रकार हैं: कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा नॉर्थ, कोहिमा साउथ, जुब्जा और केजोक्हा पुलिस थाना क्षेत्र।मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेंबा, मोकोकचुंग-द्ध, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाना क्षेत्र।

एससी-एसटी सांसदों को मिले संसद में बोलने का ज्यादा समय

केंद्रीय मंत्री मांझी ने ओम बिरला को लिखा खत

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सांसदों को बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। केंद्रीय मंत्री मांझी ने स्पीकर से इस मामले में तत्काल आवश्यक कदम उठाने की अपील की है, ताकि इन समुदायों के सांसदों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले।

16 सितंबर को अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री मांझी ने अपने आवास पर हुई एनडीए सांसदों की बैठक का हवाला दिया। उनके अनुसार, इसी बैठक में मध्य प्रदेश की खरगोन लोकसभा सीट से भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पहली बार यह चिंता जाहिर की थी। सांसद पटेल ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि यह बात केवल उन्होंने ही नहीं उठाई थी, बल्कि बैठक में मौजूद कई अन्य सांसदों ने भी इस तरह की चिंता साझा की थी। हालांकि, उन्होंने इस एक अनौपचारिक चर्चा बताया। पटेल ने जोर दिया कि सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का मौका कभी मिलता है तब कभी नहीं, और सभी सदस्य अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय मिलने की इच्छा रखते हैं। केंद्रीय मंत्री मांझी ने पत्र में कहा कि एनडीए सांसदों की बैठकें हर तीन महीने में आयोजित की जाती हैं, ताकि सांसदों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने के लिए एक मंच मिल सके। 5 अगस्त की बैठक में, खासकर एससी और एसटी समुदायों से पहली बार चुने गए कई सांसदों ने यह मुद्दा उठाया था। मांझी ने संसद में सभी सांसदों के लिए अपनी बात रखने के समान अधिकार पर जोर देकर स्पीकर से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उचित कदम उठाने का आग्रह किया है।

केंद्रीय मंत्री मांझी हाल के दिनों में एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अपने मुखर रुख को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने एससी समुदायों के भीतर उन वर्गों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए उप-वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिन्हें अब तक इसका कम फायदा मिलने का दावा होता है। इस बहस में मुसहर और भुइयां जैसे समुदायों का विशेष रूप से जिक्र हुआ है। हालांकि, एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एससी/एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अलग राय रखी है।

प्रशांत किशोर को झटका, प्रत्याशी बनने के बाद भूषण झा ने पार्टी से दिया इस्तीफा

झा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की

पटना, एजेंसी।

बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा के ठीक बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए जाने के महज 24 घंटे के अंदर प्रमुख शिक्षक नेता भूषण झा ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। जन सुराज पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए झा ने अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है।

यह घटनाक्रम मुजफ्फरपुर में हुई एक समीक्षा बैठक के बाद सामने आया, जिसमें झा ने अपने और अपने समर्थक शिक्षकों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर आरोप लगाए। झा के हटने के बाद, जन सुराज पार्टी अब शनिवार को तिरहुत शिक्षक सीट के लिए नए उम्मीदवार की घोषणा करने वाली है। जन सुराज पार्टी छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए, झा ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी बात रख रहे थे, तो उनका समर्थन करने वाले शिक्षकों को समीक्षा बैठक की रिकॉर्डिंग करने से रोका गया।

उन्होंने दावा किया कि उन पर पार्टी द्वारा तय की गई बातों के मुताबिक बोलने का दबाव डाला जा रहा था। झा ने कहा कि उन्हें यह बात आपत्तिजनक लगी और साथी शिक्षकों के सुझावों के बाद, उन्होंने जन सुराज पार्टी छोड़ने और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह बैठक 25 सितंबर को मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक होटल में हुई, जिसमें प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। बैठक के बाद ही झा ने पार्टी छोड़ने और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने बैठक में अपने और अपने समर्थक शिक्षकों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर कई आरोप भी लगाए।

बता दें जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद की आठ सीटों में से तीन के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इन सीटों के लिए चुनाव 23 अक्टूबर को होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी। पार्टी ने बाकी पांच सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही 20 सितंबर को कर दी थी।

मतदाता पंजीकरण में आयोग का बड़ा बदलाव, दीपके ने उठाया देरी पर सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इस नए अभियान के तहत, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, या जो वर्ष की पहली जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह मतदाता सूची के नियमित संशोधन का इंतजार किए बिना अपना पंजीकरण करा सकता है। यह कदम उन लाखों युवाओं और छूट गए मतदाताओं के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है जो पहले लंबी प्रक्रिया के कारण इंतजार करते थे।

हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया है। दीपके ने पोस्ट साझा कर चुनाव आयोग से पूछा,.....अब तक क्यों नहीं किया था? उन्होंने आयोग पर दबाव में आकर निर्णय लेने का आरोप लगाया है। दीपके ने इसके पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी और इस्तीफा न होने पर मुंबई में प्रदर्शन की धमकी भी दी थी। उनकी इस एक्स पोस्ट पर कई समर्थकों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को दोहराया है।

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस पहल को मतदाता सूचियों को नियमित रूप से अपडेट करने की तय प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के साथ मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, निर्धारित तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और मतदाता बनने के लिए अयोग्य घोषित न होना आवश्यक है। आयोग का कहना है कि इस कदम से अधिक से अधिक योग्य नागरिक बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।

महाराष्ट्र के 265 तालुक सूखा घोषित, 75 फीसदी में अब सूखे जैसे हालात

सीएम देवेंद्र फडणवीस सूखे से निपटने के कई उपायों की घोषणा की

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सूखे से प्रभावित किसानों और नागरिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 358 तालुकों में से 265 में सूखा घोषित किया है, जिन 265 तालुकों में ट्रिगर-1 के मानक पूरे हुए हैं, उन्हें सूखा-प्रभावित घोषित किया है। इससे पता चलता है कि राज्य के करीब 75 फीसदी तालुकों में अब सूखे जैसे हालात हैं। इसके अलावा सीएम ने सूखे से निपटने के कई उपायों की घोषणा की है। इसके तहत लैंड रेवेन्यू में छूट, फसल लोन का रीस्ट्रक्चर, खेती से जुड़े लोन की रिकवरी पर रोक, खेती के पंपों के मौजूदा बिजली बिल में छूट, स्कूल-कॉलेज के छात्रों की परीक्षा शुल्क में छूट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत नियमों में ढील देकर काम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा जहां भी जरूरी होगा वहां पीने के टैंकर पहुंचाए जाएंगे। किसानों के खेती के पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, खेती पर निर्भर किसानों-खेती मजदूरों को अनाज मिलेगा, जानवरों के लिए चारा, बड़े पैमाने पर पानी बचाने का काम भी किया जाएगा। पिछले आदेश के मुताबिक पेयजल और जानवरों के लिए पानी की प्लानिंग जारी रहेगी। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पंचनामा प्रक्रिया तुरंत पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही फसलों की हालत दिखाने वाली तस्वीरें और जीपीएस से डेटा इकट्ठा करने के आदेश जारी किए हैं।

इसके पहले 24 सितंबर वाशिम दौरे पर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार जल्द ही प्रभावित इलाकों में गंभीर सूखा घोषित करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी करेगी। साथ ही खेती-किसानी के बढ़ते संकट से जूझ रहे राज्य में उन सभी पात्र किसानों को फसल कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा, जो पिछली योजनाओं में छूट गए थे। सीएम ने गांव में किसानों को संबोधित करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया था कि सरकारी तंत्र ग्रामीण राहत कार्यों को प्राथमिकता देगा। सीएम ने कहा था कि आर्थिक मदद के अलावा, राज्य प्रशासन पीने के पानी की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने, मवेशियों के लिए चारा बांटने और फसल के नुकसान का आकलन तेजी से करने के लिए आपातकालीन उपाय कर रहा है।